page 1 and 8 may 20_page 1 Mar 25 final ds.qxd 5/20/2026 2:15 AM Page 1

epaper.dehatsandesh.com

3 श्रीनगर में विभिन्न पेंशन और कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

5 विकेट आसान नहीं था, इसलिए अंत तक टिके रहना जरूरी था: ईशान किशन

8 जनगणना 2027 के तहत सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान ने पकड़ी रफ्तार

मौसम जम्मू — न्यूनतम 25 — अधिकतम 38

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-121 | जम्मू तवी, बुधवार 20 मई, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

देश नक्सलवाद से मुक्त हुआ, उसी तरह आपराधिक मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करना है : अमित शाह

> यह बहुत हर्ष का विषय है कि यह बैठक बस्तर में आयोजित की जा रही है और इससे पहले ही आज पूरा बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है

जगदलपुर, 19 मई । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली की तीनों नवीन न्याय संहिता पर बहुत अच्छा अमल हुआ है। गंभीर अपराधों में शासन को गंभीरता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब भी इसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके क्रियान्वयन पर हमें बल देना होगा। गृह मंत्री ने कहा कि जिस तरह से हमने देश को नक्सलवाद से मुक्त किया है, उसी तरह से 3 साल में हर आपराधिक मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट तक अंजाम देने का लक्ष्य हमें 2029 से पहले पूरा करना है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित इन सदस्य राज्यों और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह बैठक केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की मेज़बानी में आयोजित की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बहुत हर्ष का विषय है कि यह बैठक बस्तर में आयोजित की जा रही है और इससे पहले ही आज पूरा बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आज भारत के नक्सल मुक्त होने का संपूर्ण श्रेय हमारे सुरक्षाबलों के जवानों के परिश्रम और बहादुरी को जाता है। हमारी एजेंसियों ने बहुत सटीकता के साथ इनपुट एकत्र किए, सभी राज्यों के पुलिसबलों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफएस) के साथ मिलकर हर इनपुट पर सटीक कार्रवाई करने से संबंधित समयबद्ध निर्णय किए। इसके साथ ही सभी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के सभी विभागों ने नक्सलमुक्त हुए क्षेत्रों में विकास को पहुंचाने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र लगभग पांच दशक से विकास की दौड़ में पिछड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इन क्षेत्रों को विकास के मामले में देश के बाकी क्षेत्रों के समकक्ष नहीं ले आते, तब तक हमारी लड़ाई समाप्त नहीं होगी। केन्द्रीय गृह मंत्री ने पूरे देश के नक्सल मुक्त होने के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन किया।

भारत-नॉर्डिक देशों ने आतंकवाद पर 'नो कम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड' का दिया संदेश : मोदी

भारत-नार्डिक शिखर सम्मेलन: हरित विकास, प्रौद्योगिकी और निवेश बढ़ाने पर बनी सहमति

ओस्लो, 19 मई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक तनाव और संघर्ष के मौजूदा दौर में भारत और नॉर्डिक देश नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने तथा आतंकवाद के खिलाफ ''नो कम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड'' की नीति पर एकजुट हैं।

प्रधानमंत्री ने नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि यूक्रेन, पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों में जारी संघर्षों के बीच भारत और नॉर्डिक देश शत्रुता की शीघ्र समाप्ति तथा स्थायी शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार आवश्यक भी है और अत्यंत जरूरी भी। मोदी ने कहा कि लोकतंत्र, कानून के शासन और बहुपक्षवाद के प्रति साझा प्रतिबद्धता भारत और नॉर्डिक देशों को स्वाभाविक साझेदार बनाती है। प्रौद्योगिकी और स्थिरता के क्षेत्र में साझा प्राथमिकताएं दोनों पक्षों के बीच सहयोग के व्यापक अवसर पैदा कर रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आठ वर्ष पहले भारत-नॉर्डिक प्रारूप की स्थापना की गई थी और पिछले कुछ वर्षों में संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग चार गुना बढ़ा है, जबकि नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश

> नॉर्डिक देशों के निवेश फंड भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं और तेज़ी से बढ़ते व्यापार तथा निवेश ने भारत के साथ-साथ नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी सकारात्मक योगदान दिया है तथा हजारों नई नौकरियां पैदा की हैं।

में करीब 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के निवेश फंड भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं और तेजी से बढ़ते व्यापार तथा निवेश ने भारत के साथ-साथ नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी सकारात्मक योगदान दिया है तथा हजारों नई नौकरियां पैदा की हैं। मोदी ने कहा कि अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य ईएफटीए देशों के साथ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता लागू किया गया है। इसके अलावा हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी हुआ है, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भागीदार हैं। इन महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों से भारत-नॉर्डिक संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी।

खबर संक्षेप

उच्च न्यायालय ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति को सांकेतिक प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दी

जम्मू, 19 मई । जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर 2025 से उच्च न्यायालय के कई अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति को सांकेतिक प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दे दी है। रजिस्ट्रार जनरल एम.के. शर्मा द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार यह निर्णय प्रशासनिक कैडर में इस वर्ष जनवरी और फरवरी में जारी विभिन्न उच्च न्यायालय आदेशों के माध्यम से पदोन्नत किए गए विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद लिया गया।

आदेश में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा विधिवत अनुमोदित उच्च न्यायालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति समिति ने संकल्प पारित होने की तिथि से सांकेतिक पदोन्नति लाभ प्रदान करने की मंजूरी दी है।

हालांकि यह लाभ रजिस्ट्रार अजय शर्मा, उप रजिस्ट्रार दलीप राजदान और शाजी भट तथा सहायक रजिस्ट्रार असीमा इलियास, इम्तियाज अहमद वानी और नजीर अहमद गनई सहित 6 अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

बजट सत्र के बाद संसदीय समितियों के जम्मू कश्मीर दौरे तेज

श्रीनगर, 19 मई। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में बजट सत्र के बाद संसदीय समितियों के लगातार दौरे देखने को मिल रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 50 दिनों में संसद की चार विभागीय स्थायी समितियां कश्मीर घाटी का दौरा कर चुकी हैं। इन समितियों ने राष्ट्रीय स्तर तथा जम्मू कश्मीर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, बाल विकास, युवा और खेल संबंधी विभागीय स्थायी समिति ने बजट सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का दौरा किया। समिति ने घाटी में शिक्षा सुधार, युवाओं की भागीदारी और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए दो दिवसीय अध्ययन दौरा किया। मई के पहले सप्ताह में सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी विभागीय स्थायी समिति ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। समिति ने वित्तीय साक्षरता, डिजिटलीकरण, वस्तु एवं सेवा कर सुधार, पेंशन विनियमन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की प्रगति, बीमा कवरेज तथा शिकायत निवारण जैसे विषयों की समीक्षा की। इसके बाद आवास एवं शहरी मामलों संबंधी विभागीय स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी कर रहे हैं, ने केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया और स्मार्ट सिटी सहित अन्य शहरी परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों संबंधी विभागीय स्थायी समिति ने 10 मई से 15 मई तक जम्मू कश्मीर का दौरा किया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

पुलवामा में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में शामिल हुए उपराज्यपाल

श्रीनगर, 19 मई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज पुलवामा में नशे के खिलाफ जन आंदोलन में शामिल हुए और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से नशे के दुरुपयोग के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी को मिलकर नशा और आतंक के नेटवर्क को खत्म करना होगा तथा युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाना होगा। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर में जनजागरण की नई लहर देखने को मिली है। बारामुला में हजारों लोगों को नशे के खिलाफ आवाज उठाते देखा गया। इसी तरह जम्मू, सांबा, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर और अन्य जिलों में युवा और अभिभावक इस लड़ाई के लिए पूरी दृढ़ता के साथ आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 39 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में लोग एक-दूसरे का सहारा बने हैं और लंबे समय से फैली चुप्पी अब टूटने लगी है। आज

> नशीले पदार्थ न केवल युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं बल्कि आतंकवाद को वित्त पोषित कर रहे-उपराज्यपाल

यह चुप्पी नशे के खिलाफ एक सामूहिक और बुलंद आवाज में बदल चुकी है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह लड़ाई भय, लालच और विनाश से संचालित नशा-आतंक नेटवर्क के खिलाफ है। केवल पुलवामा में ही हाल के दिनों में 11 हजार से अधिक स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 48 नशा तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा 56 नशा कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रशासन सीधे आतंक की

जड़ों पर प्रहार कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई दशकों तक जम्मू कश्मीर में नशा तस्करी को केवल स्थानीय अपराध माना जाता रहा, लेकिन अब लोगों को समझना होगा कि नशा तस्कर और आतंकवादी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि नशा तस्कर युवाओं का भविष्य बर्बाद करके धन कमाते हैं और आतंकी संगठन उसी धन का इस्तेमाल आतंकवाद और कट्टरता फैलाने में करते हैं। नशा बेचने वाला हर सौदा न केवल एक युवा का जीवन बर्बाद करता है, बल्कि निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए भी धन उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि जब नशा तस्कर पैसा कमाते हैं, तब हमारे युवा अपना भविष्य खो देते हैं और वही धन आतंकवादियों को हथियार उपलब्ध कराने में इस्तेमाल होता है। उन्होंने दोहराया कि उनका संकल्प अडिग है और जम्मू कश्मीर की धरती से नशा तस्करों और नशा कारोबारियों को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। उपराज्यपाल ने नशा-आतंक नेटवर्क से जुड़े लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब वे कहीं भी छिप नहीं सकते और कानून लागू करने वाली एजेंसियां लगातार उनके पीछे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन उन्हें उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों से भी खोज निकालेगा। यह अभियान केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नशा-आतंक के पूरे साम्राज्य और उसकी जड़ों को समाप्त किया जाएगा।

वार्षिक मचैल माता यात्रा के लिए सभी विभागों को निकट समन्वय में काम करने के निर्देश

श्रीनगर, 19 मई । जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने मंगलवार को किश्तवाड़ जिले में वार्षिक मचैल माता यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। यात्रा इस साल अगस्त में शुरू होने वाली है। आवश्यक सेवाओं की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने और तीर्थयात्रा मार्ग पर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण बनाए रखने के लिए सभी विभागों को निकट समन्वय में काम करने के निर्देश जारी किए गए।

मुख्य सचिव ने यात्रा के सुरक्षित और परेशानी मुक्त संचालन की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। डुल्लू ने यात्रा मार्ग पर पिछले साल बादल फटने के बाद जारी

निर्देशों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। पिछले साल 14 अगस्त को मचैल माता मंदिर के प्रवेश द्वार चिसोती गांव में बादल फट गया था, जिसमें 63 लोग मारे गए थे। ज्यादातर श्रद्धालु थे कई अन्य घायल हो गए थे और लगभग 30 लोग लापता हो गए थे। डुल्लू को ऑनलाइन और आरएफआईडी-आधारित पंजीकरण प्रणालियों की शुरूआत आपदा शमन पहल, वास्तविक समय के मौसम अलर्ट के लिए स्वचालित वर्षा गेज (एआरजी) और स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) की स्थापना और विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के विकास जैसे उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया जिसका उद्देश्य यात्रा अवधि के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करना है।

जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने बैठक को अवगत कराया कि भक्तों की अपेक्षित भीड़ को पूरा करने के लिए किश्तवाड़ मुख्यालय, गुलाबगढ़, चिशोती और मचैल सहित विभिन्न स्थानों पर आवास की विस्तृत व्यवस्था की जा रही है। सरकारी आवास निजी आवास सुविधाएं, होमस्टे और टेंट आवास को बढ़ाया जा रहा है, जबकि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए मचैल में एक समर्पित टेंट सिटी भी स्थापित की जा रही है। 100 प्रतिशत ऑनलाइन पंजीकरण और आरएफआईडी सक्षम ट्रैकिंग तंत्र के कार्यान्वयन के माध्यम से भीड़ प्रबंधन और तीर्थयात्रियों की वास्तविक समय की निगरानी पर विशेष जोर दिया गया।

पेट्रोल-डीजल और सीएनजी कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ दिल्ली में बुधवार को प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

नई दिल्ली, 19 मई । कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बुधवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन के नेतृत्व में यह प्रदर्शन कोटला मुबारकपुर क्षेत्र के पिलिंजी गांव में आयोजित किया जाएगा।

कांग्रेस ने अपने अभियान को 'कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल' नाम दिया है। पार्टी की ओर से बताया गया कि लगातार बढ़ती ईंधन और रसोई गैस की कीमतों ने आम लोगों का घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। महंगाई के कारण मध्यम वर्ग, श्रमिक, ऑटो चालक, टैक्सी चालक और निम्न आय वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

पार्टी के अनुसार यह प्रदर्शन बुधवार, 20 मई को शाम 6:30 बजे कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित पिलिंजी गांव, कोटला मुबारकपुर में आयोजित होगा। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के भी शामिल होने की संभावना जताई गई है।

उल्लेखनीय है कि 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर तीन रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये और डीजल 90.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया।

ईओडब्ल्यू कश्मीर ने 93 लाख रुपये की भूमि धोखाधड़ी मामले में तलाशी ली

श्रीनगर, 19 मई । जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने प्रवासी भूमि और खड़े पेड़ों से संबंधित फर्जी समझौतों से जुड़े 93 लाख रुपये के भूमि धोखाधड़ी मामले में बडगाम जिले में घर की तलाशी ली। अधिकारियों के अनुसार पुलिस स्टेशन ईओडब्ल्यू कश्मीर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 340 और 61(2) के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 17/2026 के संबंध में बडगाम के सेमसान इलाके में तलाशी ली गई। यह मामला धोखाधड़ी से संबंधित है जिसमें जावलपोरा, बडगाम के आरोपी गुलाम मोहि-उद-दीन डार और बेंगलुरु उत्तर, कर्नाटक के सूम नाथ कौल जो वर्तमान में जानीपुर जम्मू में रहते हैं शामिल हैं। जांच से पता चला कि शिकायतकर्ता को कथित तौर पर फर्जी समझौतों के माध्यम से पुलवामा जिले के द्रुसु में पांच कनाल प्रवासी भूमि और बिजबेहरा में 300 खड़े पेड़ खरीदने के लिए प्रेरित किया गया था।

जम्मू-कश्मीर में 19-21 मई तक कई स्थानों पर बारिश, तूफान, तेज़ हवाएँ चलने की संभावना

श्रीनगर, 19 मई । मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 19 से 21 मई तक पूरे जम्मू-कश्मीर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है साथ ही हल्की बारिश, गरज के साथ बौछारें, तेज हवाएं और कई स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है मुख्य रूप से दोपहर और शाम के समय। मौसम विभाग के अनुसार आमतौर पर 22 से 25 मई तक पूर्वाह्न के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है जबकि दोपहर के समय अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

'ऑपरेशन सिंदूर' ने भारत की स्मार्ट शक्ति का प्रदर्शन किया : सेना प्रमुख

जम्मू, 19 मई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' भारत की स्मार्ट शक्ति का संतुलित प्रदर्शन था। उन्होंने कहा कि इस सैन्य कार्रवाई में सटीक हमले, रणनीतिक संदेश और कूटनीतिक संकेतों का समन्वित राष्ट्रीय जवाब देखने को मिला।

यहां सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज द्वारा आयोजित सुरक्षा से समृद्धि - सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट शक्ति विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि इस अभियान ने दिखाया कि किस प्रकार सैन्य क्षमता को व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ जोड़ा जा सकता है। उन्होंने पिछले वर्ष 6 और 7 मई की रात को चलाए गए अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने 22 मिनट की सटीक कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर मौजूद आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और

आर्थिक दृढ़ता का एक संयुक्त राष्ट्रीय उदाहरण था। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करने के साथ-साथ लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक सोच को भी चुनौती दी। वहीं 88 घंटे बाद कार्रवाई रोकने का फैसला भारत के संतुलित और सोच-समझकर उठाए गए कदम को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 88 घंटे बाद जानबूझकर कार्रवाई रोकना स्मार्ट शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसमें यह स्पष्ट था कि किस स्तर पर और कितनी ताकत का इस्तेमाल करना है। गौरतलब है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। इस अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट सहित पाकिस्तान के नौ आतंकवादी ठिकानों तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद शिविरों पर समन्वित तीनों सेनाओं की कार्रवाई के तहत सटीक निर्देशित हथियारों से हमला किया। अपने संबोधन में जनरल द्विवेदी ने बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय अव्यवस्था, अविश्वास और गठबंधनों में विभाजन के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया से यह वादा किया गया था कि समृद्धि के कारण शक्ति आधारित राजनीति समाप्त हो जाएगी, लेकिन अब शक्ति राजनीति का इस्तेमाल समृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है।

जीएमसी जम्मू ने डेंगू को लेकर परामर्श जारी किया, स्वयं दवा लेने से बचने की सलाह

जम्मू, 19 मई। सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू ने डेंगू प्रबंधन को लेकर विस्तृत जन परामर्श जारी करते हुए लोगों से मच्छर जनित इस बीमारी के प्रति सतर्क रहने और लक्षण गंभीर होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की अपील की है। अस्पताल ने चेतावनी दी है कि डेंगू वायरस के दूसरे प्रकार से दोबारा संक्रमण होने पर गंभीर जटिलताओं, आंतरिक रक्तस्राव और अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा काफी बढ़ जाता है।

जीएमसी द्वारा जारी परामर्श के अनुसार डेंगू बुखार संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो डेंगू वायरस के चार प्रकारों में से किसी एक को वहन करता है। यह संक्रमण सामान्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, हालांकि दुर्लभ मामलों में गर्भवती महिला से शिशु तक पहुंच सकता है।

जीएमसी जम्मू के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि पहली बार डेंगू संक्रमण आमतौर पर हल्का होता है, लेकिन दूसरे प्रकार के वायरस से दोबारा संक्रमण होने पर गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। मच्छर काटने के चार से दस दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं और तीन से सात दिन तक बने रह सकते हैं। इनमें तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे

दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, मतली, उल्टी, त्वचा पर चकत्ते और अत्यधिक कमजोरी शामिल हैं।

परामर्श में कहा गया है कि लगभग हर 20 डेंगू मरीजों में से एक को शुरुआती लक्षण कम होने के बाद गंभीर डेंगू हो सकता है। जिन लोगों को पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी, सांस लेने में दिक्कत, मसूड़ों या नाक से खून आना, उल्टी या मल में खून दिखाई देना या अत्यधिक थकान महसूस हो, उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

जीएमसी जम्मू ने बताया कि डेंगू प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। वयस्क मरीजों के लिए जीएमसी अस्पताल में और बच्चों के लिए एसएमजीएस अस्पताल में अलग वार्ड बनाए गए हैं।

साभार : अशोक कुमार मुनड़ेतिया

रंगबिरंगे फूलों की घाटी

मनाली

आग बरसाते जून के महीने में पहाड़ी वादियों की ठंडक तन और मन को बेहद आराम देती है। यदि आप ठंडे और शांत माहौल की तलाश में हैं तो भी मनाली आपको खूब भाएगा। यही सोचकर भारी संख्या में पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख कर लिया है। आप भी कहीं जाने की बात सोच रहे हैं तो आपके लिए हिमाचल प्रदेश का मनाली एक अच्छी जगह साबित हो सकती है। आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपके लिए यहां ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, पैरा ग्लाइडिंग आदि की व्यवस्था मिल जाएगी।

प्रकृति ने मनाली को खुले हाथों से नूर बख्शा है। कुल्लू घाटी के प्रमुख पर्यटक स्थल मनाली में आकर हर कोई अपने आपको स्वर्ग में पाता है। हरी भरी वादियों ऊंचे-नीचे पहाड़ों पर दूर-दूर तक दिखाई देते देवदार के छोटे-बड़े पेड़ प्राकृतिक सौंदर्य को दोगुना कर देते हैं। इनके बीच घुमावदार पहाड़ी पगडंडियों पर चलते लोगों को देखकर खुद भी ट्रैकिंग का मन कर आता है।

दिल्ली से लगभग साढ़े पांच सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनाली को रंगबिरंगे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। दिसंबर के महीने में यहां हरियाली दूर-दूर तक देखने को नहीं मिलती। कारण है कि पहाड़ों, पेड़ों और घरों पर बर्फ की सफेद चादर जो फैली होती है।

गर्मी के मौसम में यहां का तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। लेकिन सर्दी के मौसम में ज्यादातर दिनों में सात डिग्री से नीचे पहुंच जाता है। यहां आने के लिए गर्मी के लिहाज से मार्च से जून और ठंड के लिहाज से अक्टूबर से फरवरी के महीने ज्यादा ठीक रहते हैं।

देखने लायक खास स्थल :

कुल्लू घाटी का असली सौंदर्य मनाली में ही देखने को मिलता है। यहां देखने और घूमने के लिहाज से बहुत से मशहूर स्थल हैं। यहां की सुरमई शाम अलसाती भोर का मजा ही कुछ और है।

कोठी : मनाली से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कोठी। यहां से पहाड़ों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहां बीस नदी का तेजी से बहता ठंडा पानी अदभुत नजारा पेश करता है।

राहला फॉल्स, मनाली सैंचुरी : कोठी से दो किमी की दूरी पर बीस नदी पर राहला फॉल्स स्थित है। यहां 50 मीटर की ऊंचाई से गिरता झरने का पानी सैलानियों को खूब लुभाता है। मनाली सैंचुरी में पर्यटक कैंपिंग के लिए पहुंचते हैं।

सोलन वैली : यहां से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोलन वैली सैलानियों को खासी आकर्षित करती है। यहां ट्रैकिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग के कैंप आयोजित किए जाते हैं। 10 से 14 फरवरी के बीच यहां सालाना विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाता है।

रोहतांग भी है मनाली के पास : मनाली के आस-पास के इलाकों में सैलानियों के लिए बहुत कुछ बिखरा पड़ा है। प्रकृति ने यहां आने वालों के लिए अपना खजाना दोनों हाथों से खोल दिया है। पहाड़ियों पर बने छोटे-छोटे घर और इनके आस-पास फैली हरियाली मन को लुभाती है। यहां से 51 किमी की दूरी पर मशहूर पर्यटक स्थल रोहतांग पास स्थित है। यहां हर साल हजारों की संख्या में सैलानी घूमने के लिए आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस तरफ पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है।

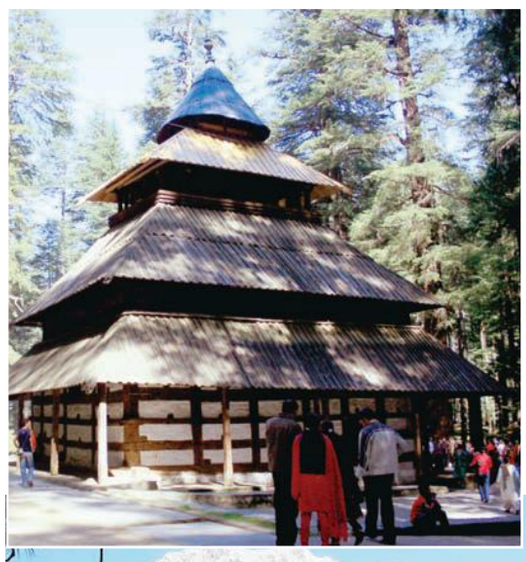

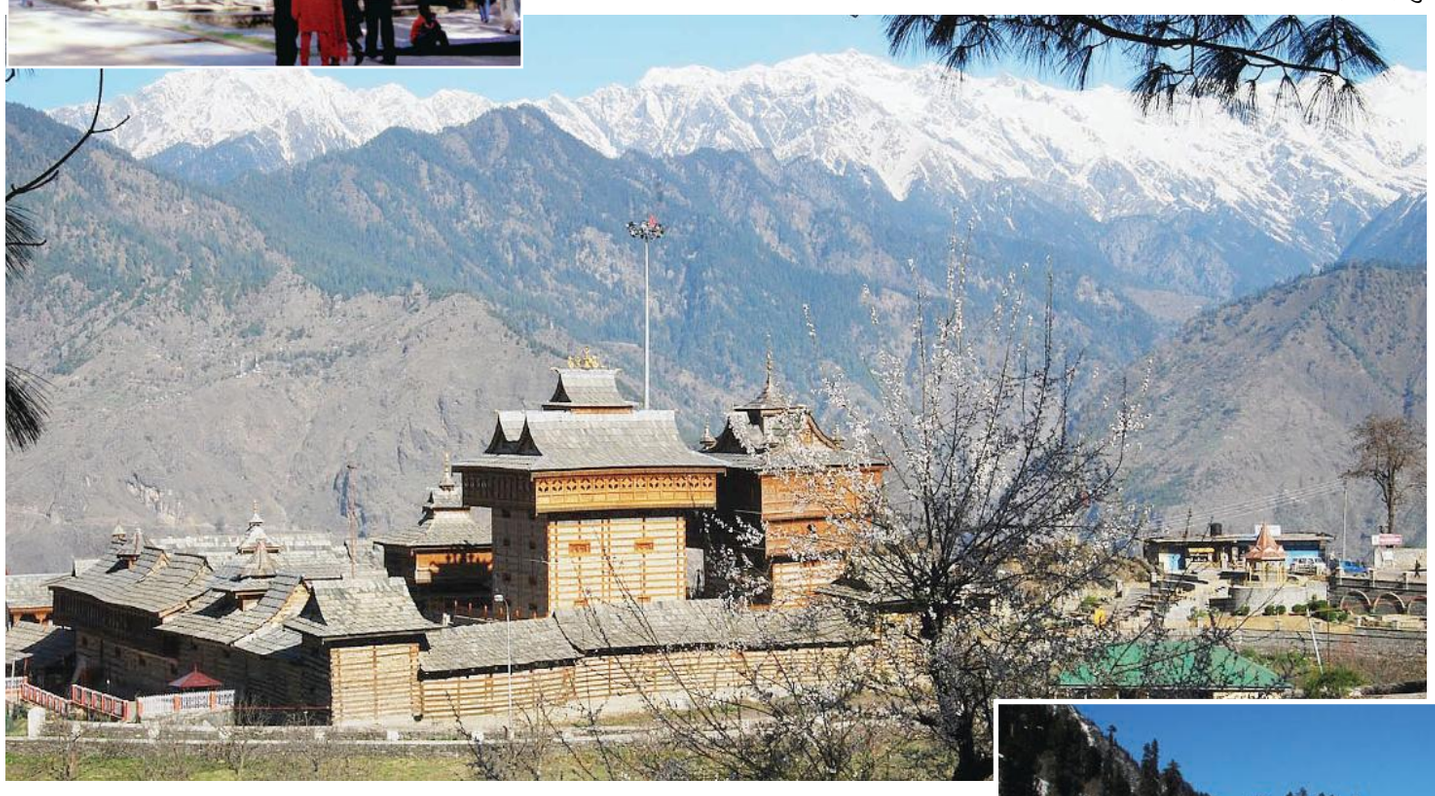

इसलिए अब सरकार ने भी इसे पर्यटन के लिए लिहाज से उपयुक्त समझा है। यह शहर समुद्रतल से 7,589 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इतिहास में इसको बुशहर नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त 51 शक्तिपीठों में से एक भीमाकाली माता का मंदिर भी इसी शहर में है। हिंदू और बौद्ध वास्तुशिल्प से निर्मित यह मंदिर लगभग 2,000 वर्ष पुराना है, मगर इसका जीर्णोद्धार कर इसको पुनः वही आकार दिया गया है।

पत्थरों और लकड़ी के इस्तेमाल से बना यह मंदिर शत-प्रतिशत भूकंपरोधी है। मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर आप हिमालय को साक्षात निहार सकते हैं। इस मंदिर के नजदीक ही आपको एक पक्षी-विहार है जिसमें यहां के राज्य-पक्षी मोनाल सहित लगभग हर प्रकार के पहाड़ी पक्षी हैं। सरकार और स्थानीय लोगों के प्रयासों से रास्तों के दोनों तरफ लगाए गए तरह-तरह के फूल लहराते हुए पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

अद्भुत पर्यटक स्थल सराहन घाटी

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और किन्नौर जिले की सीमा पर बसा सराहन स्वर्ग का एहसास कराने वाला एक सुंदर और अद्भुत पर्यटक स्थल है जो सराहन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र कई वर्षों तक पर्यटन के लिहाज से बचा रहा मगर अब

सराहन से लगभग सात किलोमीटर की दूरी पर यदि घाटी से थोड़ा नीचे उतरेंगे तो वहां आपको सतलज नदी का मनोहारी दृश्य मिलेगा। इसके अतिरिक्त सराहन से कुछ ही दूरी पर कामरू का ऐतिहासिक किला, चितकुल घाटी और बस्पा नदी जैसे अन्य पर्यटन स्थल भी हैं जहां आप आसानी आ-जा सकते हैं।

शहर अत्यधिक बड़ा न होने के कारण यहां यातायात के साधनों की आवश्यकता कम ही होती है इसलिए कुछ स्थानों पर पैदल भी घूमा जा सकता है। फिर भी यहां टैक्सी, बस आदि की सुविधा आसानी से मिल जाती है और महंगी भी नहीं है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यहां आम से खास तक, सभी के बजट के अनुसार होटल और रेस्ट हाउस आदि का भी विशेष प्रबंध किया है।

यहां आने के लिए सर्दियां उचित समय नहीं है क्योंकि इस मौसम में यहां पर तापमान शून्य से भी नीचे ही रहता है। यहां आने के लिए मार्च से जून और सितंबर से अक्टूबर का समय बहुत ही अच्छा समय है। दिन के समय यहां का तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री तक रहता है। मगर रात को ठंड बढ़ जाती है।

यदि अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो ध्यान दें कि शिमला से राष्ट्रीय राजमार्ग 22 से होते हुए रास्ते में थेयोग, नारकंडा, रामपुर और जैओरी नामक कुछ छोटे-छोटे पर्यटन स्थल भी आते हैं जहां आपको पेट्रोल पंप की सुविधा मिलेगी। शिमला से सराहन के बीच लगभग 180 किलोमीटर के इस रास्ते पर जब आप निकलेंगे तो आपका सामना देवदार के घने जंगलों, कई सारे छोटे-बड़े झरनों, खेतों एवं छोटे-छोटे अनेक गांवों से होगा।

इन गांवों से होकर जाने पर आपको उनके पारंपरिक पहनावे और संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। सराहन जाने के लिए सड़क मार्ग ही है जो शिमला से टैक्सी, जीप या बस द्वारा भी जाया जा सकता है। यह दूरी लगभग 6-7 घंटे में आसानी से तय की जा सकती है।

यह रास्ता अधिकतर सतलुज नदी के किनारे से गुजरता है, इसलिए इसकी तेज धारा आपको एक नए संगीत की से रू-ब-रू कराएगी। इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे आप सराहन के नजदीक पहुंचेगे वैसे-वैसे आपको मार्ग के किनारे अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियां भी नजर आने लगेंगी।

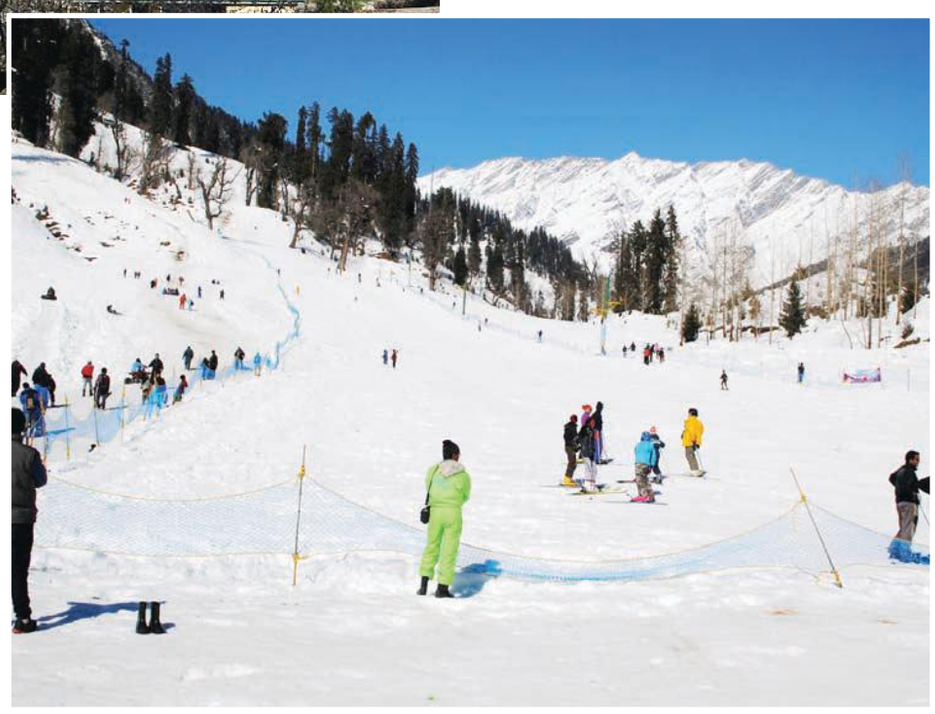

कैसे पहुंचे : मनाली जाने के लिए सड़क मार्ग से अपनी गाड़ी से या फिर बस सेवा ली जा सकती है। हवाई यात्रा करनी है तो लगभग 50 किमी से टैक्सी लेनी होगी।

यात्रा पैकेज :

यदि आने-जाने और ठहरने का कोई झंझट नहीं पालना चाहते तो कई तरह के पैकेज भी उपलब्ध हैं। तीन दिन और रात ठहरने के लिए अलग-अलग होटल में प्रति जोड़ा 11,500 रुपए से 15 हजार रुपए में ठहरना, हर दिन नाश्ता, लंच और डिनर आदि हो जाता है। 23 हजार रुपए में ठहरने, खाने के साथ लोकल साइट सीइंग, डिस्कोथेक, कॉकटेल और स्टीम या सोना बाथ की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन द्वारा खुद भी कई तरह की स्कीम दी जा रही हैं जो आप ले सकते हैं।

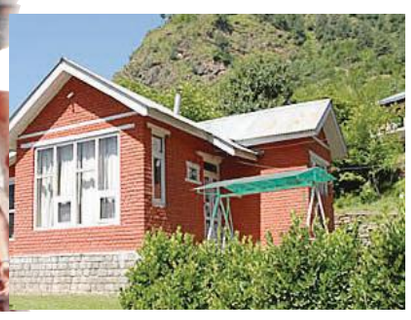

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

श्रीनगर में विभिन्न पेंशन और कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

श्रीनगर, 19 मई। श्रीनगर के उपायुक्त अक्षय लाबरू ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर के बैठक कक्ष में एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जेके समाधान, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना तथा व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना सहित विभिन्न जनकल्याण और पेंशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने श्रमिकों, किसानों, व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन सुविधा और शिकायत निवारण सहायता उपलब्ध कराने वाली योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों की विस्तृत क्षेत्रवार समीक्षा की। बैठक की शुरुआत में संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने लाभार्थियों के पंजीकरण, नामांकन, जागरूकता गतिविधियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए सभी पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि जिले में छूटे हुए लोगों का मौके पर पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि योजनाओं का अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचे। व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों की राष्ट्रीय पेंशन योजना के संबंध में उपायुक्त ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को अन्य विभागों के सहयोग से 10 जून 2026 तक योजना में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री के सलाहकार ने जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा

जम्मू, 19 मई (हि.स.)। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने आज जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत चल रहे प्रमुख अवसंरचना एवं विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की और आगामी अमरनाथ यात्रा से पहले सभी प्रमुख परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरे के दौरान सलाहकार के साथ परियोजना निदेशक डॉ. देवांश यादव, सुनील थुसू और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सलाहकार ने सबसे पहले फेम-द्वितीय पहल के अंतर्गत विकसित किए जा रहे टाटा ई-बस डिपो का दौरा किया और पीएम ई-बस सेवा परियोजना से संबंधित चल रहे कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि जम्मू शहर में पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आधुनिक इलेक्ट्रिक बस अवसंरचना विकसित की जा रही है। शहरी परिवहन अवसंरचना के आधुनिकीकरण में जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रयासों की सराहना करते हुए नासिर असलम ने अब तक की प्रगति की प्रशंसा की और अधिकारियों को पीएम ई-बस सेवा परियोजना के शीघ्र पूरा होने और उद्घाटन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी पहल जम्मू को एक स्वच्छ, हरित और अधिक व्यवस्थित शहरी केंद्र में बदल रही है और सभी विकास परियोजनाओं को मिशन मोड में तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। बाद में सलाहकार ने आगामी वेस्ट टू वंडर पार्क परियोजना का दौरा किया और पुनर्चक्रित अपशिष्ट सामग्री से निर्मित कलात्मक स्मारकों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने परियोजना में लगे कारीगरों और श्रमिकों से भी बातचीत की और उनकी रचनात्मकता और समर्पण की सराहना की। इस पहल को जम्मू शहर के लिए एक अनूठी और अभिनव उपलब्धि बताते हुए सलाहकार ने पर्यटन, पर्यावरण जागरूकता और जन मनोरंजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसी सराहनीय परियोजना शुरू करने के लिए जम्मू स्मार्ट सिटी टीम को बधाई दी। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वेस्ट टू वंडर पार्क को लगभग 11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किया जा रहा है और इसके जून 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि सलाहकार ने संबंधित अधिकारियों को अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले परियोजना को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया ताकि जम्मू आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक भी इस आकर्षण का अनुभव कर सकें।

पुलिस ने अरनिया में 14 वर्षों से लापता महिला का पता लगाकर परिवार के साथ मिलाया

जम्मू, 19 मई (हि.स.)। जम्मू पुलिस ने कई वर्षों से लापता एक महिला का पता लगाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। लापता महिला जतुन बीबी पत्नी शम्स दीन निवासी कल्याणा 22-11-2012 से लापता थी। एसएचो अरनिया डीएसपी प्रोबेशनर क़ैसर की पुलिस टीम द्वारा निरंतर प्रयासों और समर्पित जांच के माध्यम से लापता महिला का सफलतापूर्वक पता लगा लिया गया और सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसे सुरक्षित रूप से उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंप दिया गया।

परिवार के सदस्यों ने लापता महिला को उसके परिवार से मिलाने के लगातार प्रयासों और प्रतिबद्धता के लिए जम्मू पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया

18 वर्षीय नाई के धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने जांच शुरू की

श्रीनगर, 19 मई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक 18 वर्षीय नाई के धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मंगलवार को जानकारी दी कि किशोर की पहचान विशाल के रूप में हुई है जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है। अधिकारियों ने बताया कि कुपवाड़ा में धर्म परिवर्तन से संबंधित एक मामले का संज्ञान लिया गया है और संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अपुष्ट जानकारी न फैलाने की अपील की है और बताया कि मामले की जांच जारी है।

यात्री बस सड़क से फिसलकर पलटी, कंडक्टर की मौत, 19 घायल

रामबन, 19 मई (हि.स.)। मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के संगलदान पर्वतीय क्षेत्र में एक यात्री बस सड़क से फिसलकर पलट गई जिससे कंडक्टर की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना संगलदान पुलिस चौकी के पास हुई जब बस गोल के धर्म से जम्मू जा रही थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस और स्थानीय निवासियों ने बचाव अभियान शुरू किया और 19 घायलों को पास के चिकित्सा केंद्रों में पहुंचाया। मृतक की पहचान उधमपुर जिले के पनारा निवासी बस कंडक्टर आशु सिंह के रूप में हुई है।

बी.के. ट्रेडर्स ग्रुप के गोदाम में लगी भीषण आग, हार्डवेयर और सैनिटरी सामान पूरी तरह जलकर राख

बारामूला, 19 मई (हि.स.)। बारामूला के कनली बाग इलाके में स्थित बी.के. ट्रेडर्स ग्रुप के गोदाम मे देर रात भीषण आग लग गई। इस दौरान हार्डवेयर और सैनिटरी सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। गोदाम मालिक के अनुसार इस हादसे में लगभग 5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और गोदाम में रखा 100 प्रतिशत सामान तबाह हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार जैसी ही आग लगने की सूचना मिली तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों, जम्मू-कश्मीर पुलिस तथा भारतीय सेना ने मिलकर राहत और बचाव कार्य चलाया जिसकी बदौलत आसपास की रिहायशी बस्ती को बचा लिया गया। हालांकि गोदाम पूरी तरह जल गया लेकिन समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया।

सुरनकोट में बाजार जांच अभियान चलाया गया

सुरनकोट, 19 मई। तहसीलदार सुरनकोट के निर्देशों पर जेडडब्ल्यूजी क्षेत्र में नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए बाजार जांच अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान कई उल्लंघन पाए गए, जिसके बाद नियम तोड़ने वालों पर कुल 3,400 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

यह अभियान नायब तहसीलदार राजिंदर शर्मा की देखरेख में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ चलाया गया।

दल ने विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया तथा व्यापारियों को भविष्य में जुर्माने से बचने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी।

प्रशासन ने कहा कि बाजार में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस प्रकार के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

मात्र 6000 बना मौत की वजह-4 दिन में सुलझा ब्लाइंड मर्डर केस, आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद

कठुआ, 19 मई (हि.स.)। रूप सिंह हत्या मामले में कठुआ पुलिस ने त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए ब्लाइंड मर्डर केस को मात्र 4 दिनों में सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस ऑपरेशन की निगरानी एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के नेतृत्व में की गई।

एसएसपी कठुआ ने बताया कि 15/16 मई 2026 की दरम्यानी रात को थाना लखनपुर को गांव धन्ना में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की सूचना मिली। मृतक की पहचान रूप सिंह के रूप में हुई जो पेशे से ठेकेदार था। सूचना मिलते ही थाना लखनपुर में एफआईआर नंबर 51/2026 धारा 103 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में विशेष जांच टीम का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक पूछताछ की। वहीं जांच के दौरान सरदार सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी त्रिडवां तहसील व जिला कठुआ घटना के बाद से लापता पाया गया जिससे उस पर शक गहरा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी मृतक के पास मजदूरी करता था और उसके 6000 बकाया थे। इसी रकम को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था।

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गुस्से और रंजिश में आकर 15/16 मई की रात अपने पिता की 12 बोर बंदूक लेकर रूप सिंह के घर पहुंचकर खिड़की के पास सो रहे रूप सिंह पर गोली चला दी और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने कई टीमों का गठन कर जम्मू-कश्मीर समेत पड़ोसी राज्यों में लगातार छापेमारी की। हिमाचल प्रदेश पुलिस के सहयोग से मिली सूचनाओं के आधार पर आरोपी को 19 मई की सुबह करीब 7 बजे जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के संसारपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है।

वहीं मामले की आगे की जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अल्पसंख्यक मोर्चा की मासिक बैठक आयोजित, सिख समाज के लिए केंद्र सरकार की पहलों पर चर्चा

कठुआ, 19 मई (हि.स.)। कठुआ में अल्पसंख्यक मोर्चा की मासिक बैठक का आयोजन मास्टर शिंगारा सिंह की अध्यक्षता तथा जिला भाजपा अध्यक्ष उपदेश अंडोत्रा के मार्गदर्शन में किया गया। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

इस अवसर पर राजेश मेहता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिख समाज के हित में उठाए गए ऐतिहासिक कदमों और कल्याणकारी कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन, श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के भव्य आयोजन, 1984 दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के प्रयासों तथा साहिबजादों के सम्मान में 'वीर बाल दिवस' घोषित किए जाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया। बैठक के अंत में 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह' के जयघोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। साथ ही समाज में एकता, भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने का संकल्प भी दोहराया गया।

नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम

बांदीपोरा, 19 मई। एचकेएम सरकारी डिग्री कॉलेज बांदीपोरा में मंगलवार को नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों को नशे और तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना था।

कार्यक्रम प्राचार्य प्रोफेसर सुरेश कुमार डोगरा के मार्गदर्शन में आयोजित किए गए। वनस्पति विज्ञान विभाग ने रेड रिबन युवा क्लब के सहयोग से नशा मुक्ति पर व्याख्यान आयोजित किया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर मेहराजुद्दीन ताली ने नशे की बढ़ती समस्या और उसके सामाजिक, मानसिक तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की।

एयरटेल ने लॉन्च की प्रायोरिटी पोस्टपेड सेवा, ग्राहकों को मिलेगा बेहतर नेटवर्क अनुभव

जम्मू, 19 मई। भारती एयरटेल ने आज प्रायोरिटी पोस्टपेड सेवा लॉन्च करने की घोषणा की। यह नई सेवा 5जी स्लाइसिंग तकनीक का उपयोग करती है, जिससे पोस्टपेड ग्राहकों को स्थिर और बेहतर नेटवर्क का अनुभव मिलेगा। यह सेवा विशेष रूप से उन व्यस्त ग्राहकों के लिए तैयार की गई है, जो काम, मनोरंजन या ऑनलाइन सहयोग के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी पर निर्भर रहते हैं।

इस सेवा के लिए एयरटेल ने अपने 5जी नेटवर्क को नेटवर्क स्लाइसिंग तकनीक की उन्नत क्षमताओं से सशक्त बनाया है। यह तकनीक नेटवर्क को अधिक स्मार्ट और कुशल बनाते हुए अतिरिक्त क्षमता तैयार करती है, जिससे प्रायोरिटी ग्राहकों को बेहतर और निर्बाध अनुभव सुनिश्चित किया जा सकता है। नेटवर्क क्षमता को इंटेलीजेंट और डायनेमिक तरीके से विभाजित कर एयरटेल अपने पोस्टपेड ग्राहकों को अधिक स्थिर, भरोसेमंद और लगातार बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब नेटवर्क पर ट्रैफिक का दबाव अधिक हो।

GOVERNMENT OF JAMMU AND KASHMIR
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER MECHANICAL DIVISION RTIC JAMMU
Notice INVITING TENDER
e- NIT MDJ/ RTIC/06 of 2026-27 Dated 18-05-2026

For and on behalf of the "Lt. Governor of Union Territory of Jammu and Kashmir", The Executive Engineer Mechanical Division RTIC Jammu, invites online bids by e tendering mode from eligible bidders/ tenderers /firms dealing with electromechanical /electrical works.

Name of the Work	Name of the Division	Cost of Tender Document/Tender Fee(In Rs)	Earnest Money	Validity of Rates
Repair and maintenance of 02 ton capacity gate machines installed on main Tawi/Ravi Canal including replacement repairs of its various components/fixtures etc. for their continuous and smooth operations (D-7 H/R, D-20 H/R, Link Channel)	Mechanical Division RTIC Jammu	**Rs. 200.00** (Non-Refundable) In the shape of treasury Challanonly in favour of the Executive Engineer, Mechanical Division RTIC Jammu payable at Jammu **(under M.H. 0701)**	**Rs 2000/-** In the shape of CDR/FDR pledged to the Executive Engineer Mechanical Division RTIC Jammu	Bid shall be valid for 180 days

Bid documents can be seen at and downloaded from the website http://jktenders.gov.in from18-05-2026 (06:00 P.M.) and uploaded upto 02-06-2026 (1:00 P.M). The tender shall be opened on 03-06-2026 (10:00 A.M).
2. The complete bidding process will be online http://jktenders.gov.in.
3. Bids must be accompanied by cost of Tender Document and bid security/ earnest moneyas specified in column 3 & 4 of the table.The cost of tender documents should be in the form of Treasury Challan only in favour of Executive Engineer, Mechanical Division RTIC Jammu.
4. Furnishing of Hard copies of documents pertaining to e bids immediately after submission of e tenders have been dispensed with as per Govt Order No. O.M. no. A/24(2017-651) dated 07-06-2018. The same shall be obtained only from the bidder who is declared as L-1 after opening of Financial Bids.
5. The hard copy of cost of tender document in shape of Treasury Challan and Earnest Money including other relevant documents must be delivered by L-1 to the office of the Executive Engineer, Mechanical Division RTIC Jammu within 03 days of opening of tender.
6. The bid shall remain open for acceptance for a period of 180 days from the date of opening of bids. If any bidder/ tenderer withdraws his bid/ tender before the said period or makes any modifications in the terms and conditions of the bid, the said earnest money shall stand forfeited.
7. The Technical Bids of the tender document received shall be opened online in the office of Executive Engineer Mechanical Division, RTIC, Jammu on 03-06-2026 at 10:00 A.M onwards.
8. The Financial Bids of the tender document of the qualified bidders shall also be opened online in the office of the Executive Engineer Mechanical Division, RTIC, Jammuduring office hours on a convenient day.
9. Other details can be seen inside the detailed tender document.

No: MDJ/RTIC/182-85 Dated- 18-05-2026

DIP/J-2250/26
Dtd: 19-5-2026

Sd/-
Executive Engineer
Mechanical Division
RTIC, Jammu

केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में अनुवाद कौशल विकास कार्यशाला का उद्घाटन

केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान मैसूर तथा भाषा विद्यालय के सहयोग से डोगरी, हिंदी, पंजाबी और उर्दू भाषाओं पर आधारित तीन दिवसीय अनुवाद कौशल विकास कार्यशाला का उद्घाटन किया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों, शोधार्थियों और भाषा विशेषज्ञों में बहुभाषीय दक्षता को बढ़ावा देना तथा अनुवाद कौशल को मजबूत बनाना है। विशेष रूप से डोगरी, पंजाबी, हिंदी और उर्दू भाषाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

कार्यक्रम में डोगरी संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर ललित मंगोत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर यशवंत सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

अपने संबोधन में प्रोफेसर ललित मंगोत्रा ने वैज्ञानिक विषयों के अनुवाद की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली, अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और व्याख्याओं के कारण चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने वैज्ञानिक अनुवाद में शुद्धता, स्पष्टता और संदर्भ की सही समझ को आवश्यक बताया। साथ ही तकनीकी विषयों के अनुवाद से जुड़े व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वैज्ञानिक ज्ञान को विभिन्न भाषाई समुदायों तक पहुँचाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि अनुवाद केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह संस्कृतियों, परंपराओं, इतिहास और जीवन अनुभवों का भी आदान-प्रदान है।

कार्यक्रम की शुरुआत भाषा विद्यालय की अधिष्ठाता एवं कार्यशाला संयोजक प्रोफेसर वंदना शर्मा के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने कहा कि समय के साथ अनुवाद की भूमिका में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। उन्होंने यह भी कहा ह्लद्धड्डह्ल कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप है।

राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के प्रभारी अधिकारी तथा भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान मैसूर के शैक्षणिक सचिव डॉक्टर तारिक खान ने राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की दृष्टि और उद्देश्यों की जानकारी दी तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के साथ भविष्य में और अधिक सहयोग की आशा व्यक्त की। इस अवसर पर राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के संसाधन विशेषज्ञ सुनील चौधरी तथा जाफर मीर भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलसचिव प्रोफेसर यशवंत सिंह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्तमान दौर में अनुवाद की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रगति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव के बावजूद मानवीय अनुवाद की आवश्यकता सदैव बनी रहेगी, क्योंकि यह सांस्कृतिक संवेदनशीलता, भाषाई विविधता और संदर्भ की गहराई को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कार्यक्रम का समापन हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर भारत भूषण द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर के राजेश, शैक्षणिक मामलों के सह-अधिष्ठाता प्रोफेसर उदय प्रताप सहित विभिन्न विभागों के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष और शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यशाला में विभिन्न भाषाओं और विषयों से लगभग 55 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद और अनुवाद विशेषज्ञ इस कार्यशाला में संसाधन विशेषज्ञ के रूप में भाग ले रहे हैं।

संपादकीय

यात्रा के लिए सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था

यह अत्यंत आवश्यक है कि सुरक्षा बल आगामी श्री अमरनाथजी यात्रा के दौरान मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अभी से तैयारी प्रारम्भ करें। इस संदर्भ में दूरदराज़ के गांवों और बस्तियों को भी सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है, क्योंकि अतीत में आतंकवादियों ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बरती गई लापरवाही का लाभ उठाकर अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने का प्रयास किया है।

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों ने जम्मू-कश्मीर में, विशेषकर यात्रा अवधि के दौरान, शांति बनाए रखने में सकारात्मक परिणाम दिए हैं। इसलिए इस वर्ष भी इसी प्रकार के प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है, ताकि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके। यह यात्रा दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन हेतु लाखों श्रद्धालुओं के आगमन का प्रतीक है।

प्रत्येक वर्ष सरकार यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती करती है। इस वर्ष भी ऐसी खबरें सामने आई हैं कि बंगाल और असम में चुनाव ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था हेतु जम्मू-कश्मीर भेजा जाएगा। किंतु केवल अतिरिक्त जवानों की तैनाती पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ अन्य सभी आवश्यक कदम उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

इसी दिशा में सेना ने एक सराहनीय पहल करते हुए रामबन जिले में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (एनएच-44) के आसपास स्थित कब्बी, गंधरी, खट्टर, मुगाला और भटनी गांवों के ग्राम रक्षा समूहों (वीडीजी) के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर तैयारी को मजबूत करना, सुरक्षा बलों के साथ समन्वय बढ़ाना तथा वार्षिक यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना था। यह यात्रा आस्था, एकता और राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतीक मानी जाती है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में फायरिंग की स्थिति, हथियारों के संचालन तथा फायर एंड मूवजैसी व्यावहारिक अभ्यास प्रक्रियाएं शामिल थीं, जिससे प्रतिभागियों को आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया देने तथा अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखने में सहायता मिल सके। इस प्रकार के कदम यात्रा के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं और वीडीजी के पुनर्जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं।

चूंकि यात्रा प्रारम्भ होने में अभी कुछ दिन शेष हैं, इसलिए सेना को चाहिए कि वह पूरे क्षेत्र में मौजूद सभी वीडीजी को इसी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करे, ताकि इस स्वयंसेवी बल का अधिकतम उपयोग किया जा सके। यह बल उन क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करने तथा राष्ट्रविरोधी तत्वों का मुकाबला करने में सहायक हो सकता है, जहां सुरक्षा बलों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम है। यद्यपि देखने में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वीडीजी की भूमिका सीमित है, किंतु वास्तव में उनकी मौजूदगी दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों के भीतर विश्वास उत्पन्न करती है तथा हिंसा फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इटली और भारत-इंडो-भूमध्यसागरीय क्षेत्र के लिए एक रणनीतिक साझेदारी

-नरेंद्र मोदी, भारतके प्रधानमंत्री और जॉर्जिया मेलोनी, इटली गणराज्य मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष

हमारा दृष्टिकोण भारत की विशाल डिजिटल क्षमता को इटली की नैतिक और औद्योगिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है, ताकि तकनीक मानव गरिमा की सेवा कर सके।सुरक्षित डिजिटल सहयोग, क्षमता निर्माण और मजबूत साइबर ढांचे से जुड़ी श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करके, हम एक ऐसा खुला, भरोसेमंद और समान डिजिटल वातावरण बनाना चाहते हैं, जिसमें हर देश एआई का उपयोग कर सके और उससे लाभ उठा सके। यही सोच इटली की जी7 अध्यक्षता और 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के निष्कर्षों का मुख्य आधार है। एआई को इंसानों की ओर से इंसानों के लिए बनाई गई तकनीक मानने का अर्थ है यह स्पष्ट करना कि तकनीक न तो मनुष्य की जगह ले सकती है और न ही उसके मूल अधिकारों को कमजोर कर सकती है। इसका उपयोग जनमत को प्रभावित करने या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए भी नहीं होना चाहिए।

भारत और इटली के संबंध अब एक निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में अभूतपूर्व तेजी से विस्तार हुआ है। यह संबंध केवल सौहार्दपूर्ण मित्रता तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों तथा भविष्य के साझा दृष्टिकोण पर आधारित एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। ऐसे समय में, जब पूरी दुनिया की व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, इटली और भारत की साझेदारी उच्च राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर लगातार संवाद से आगे बढ़ रही है। यह संबंध अब एक नए और अधिक व्यापक स्तर पर पहुंच रहा है, जिसमें दोनों देशों की आर्थिक ताकत, सामाजिक रचनात्मकता और हजारों वर्षों पुरानी सभ्यतागत विरासत शामिल है।

हमारा सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि देश कितनी क्षमता से नवाचार करें, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करें और अपनी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करें। इसी उद्देश्य से हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा तथा विविध बनाने का संकल्प लिया है, ताकि नए लक्ष्यों को हासिल किया जा सके और दोनों देशों की पूरक शक्तियों का बेहतर उपयोग हो सके। हम इटली की डिजाइन क्षमता, बेहतरीन विनिर्माण कौशल और विश्वस्तरीय सुपरकंप्यूटर तकनीक—जो उसे एक औद्योगिक महाशक्ति बनाती है—को भारत की तेज़ आर्थिक वृद्धि, इंजीनियरिंग प्रतिभा, बड़े पैमाने की क्षमता, नवाचार और 100 से अधिक यूनिकॉर्न तथा 2 लाख स्टार्ट-अप वाले उद्यमी इकोसिस्टम के साथ जोड़कर एक शक्तिशाली तालमेल बनाना चाहते हैं।

यह केवल दो व्यवस्थाओं का साधारण मेल नहीं है, बल्कि ऐसा साझा मूल्य निर्माण है जिसमें दोनों देशों की औद्योगिक ताकतें एक-दूसरे को और अधिक मजबूत बनाती हैं।

यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश बढ़ाने का रास्ता खोलता है। हमारा लक्ष्य 2029 तक भारत और इटली के बीच व्यापार को 20 अरब यूरो से आगे ले जाना है। इसमें रक्षा एवं एयरोस्पेस, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पुर्जे, रसायन, दवाइयां, वस्त्र, कृषि-खाद्य क्षेत्र और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा। मेड इन इटली हमेशा से दुनिया भर में उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है, और आज इसका स्वाभाविक तालमेल मेक इन इंडियापहल के उच्च गुणवत्ता वाले लक्ष्यों के साथ दिखाई देता है। इसी संदर्भ में, भारत के लिए उत्पादन में इतालवी कंपनियों की बढ़ती रुचि और इटली में भारतीय उद्योगों की बढ़ती मौजूदगी — जो अब दोनों पक्षों से मिलाकर 1000 से अधिक हो चुकी है — एक सकारात्मक संकेत है। यह हमारी सप्लाई चेन के एकीकरण को और मजबूत करेगी।तकनीकी नवाचार हमारी साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। आने वाले दशकों में दुनिया एक बड़े तकनीकी बदलाव के दौर से गुजरेगी, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में तेज प्रगति होगी। भारत का तेज़ी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या, तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता—इन क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक बनाती है।

दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के बीच बढ़ती साझेदारी भी इसे मजबूती देगी।

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पहले से ही दुनिया के कई देशों, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों, के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है।

विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आज हमारे समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रही है। इटली और भारत लंबे समय से इस दिशा में सहयोग कर रहे हैं, ताकि एआई का विकास जिम्मेदार और मानव-केंद्रित हो।

भारत और इटली एआई को समावेशी विकास का एक शक्तिशाली माध्यम भी मानते हैं, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आसान, बहुभाषी तकनीकों के जरिए एआई सामाजिक और डिजिटल खाइयों को कम कर सकता है, न कि उन्हें और बढ़ा सकता भारत के मानव विज़न- यानी तकनीक के केंद्र में मानव को रखने की सोच और इटली की मानव-केंद्रित एल्गोर-एथिक्स की अवधारणा, जो उसकी मानवतावादी परंपरा पर आधारित है, पर आगे बढ़ते हुए हमारी साझेदारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम बने।

हमारा दृष्टिकोण भारत की विशाल डिजिटल क्षमता को इटली की नैतिक और औद्योगिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है, ताकि तकनीक मानव गरिमा की सेवा कर सके।सुरक्षित डिजिटल सहयोग, क्षमता निर्माण और मजबूत साइबर ढांचे से जुड़ी श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करके, हम एक ऐसा खुला, भरोसेमंद और समान डिजिटल वातावरण बनाना चाहते हैं, जिसमें हर देश एआई का उपयोग कर सके और उससे लाभ उठा सके। यही सोच इटली की जी7 अध्यक्षता और 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के निष्कर्षों का मुख्य आधार है। एआई को इंसानों की ओर से इंसानों के लिए बनाई गई तकनीक मानने का अर्थ है यह स्पष्ट करना कि तकनीक न तो मनुष्य की जगह ले सकती है और न ही उसके मूल अधिकारों को कमजोर कर सकती है। इसका उपयोग जनमत को प्रभावित करने या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए भी नहीं होना चाहिए।

आज की तेजी से जुड़ी हुई दुनिया में स्वतंत्रता और मानव गरिमा की रक्षा का हमारा दृष्टिकोण इसी चुनौती पर आधारित है।हमारा सहयोग अंतरिक्ष क्षेत्र तक भी फैला हुआ है। अंतरिक्ष अनुसंधान और सैटेलाइट तकनीक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति तथा इटली की एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता, संयुक्त परियोजनाओं और नई पीढ़ी की तकनीकों के विकास के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है।राष्ट्रों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और स्थिरता बेहद आवश्यक हैं। इसलिए इटली और भारत रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक तकनीकों जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। हमारा सहयोग महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, तथा आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी चुनौतियों के खिलाफ मजबूती बढ़ाने में मदद करेगा।

ऊर्जा हमारी साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण आधार है। दुनिया में ऊर्जा के विविध स्रोतों की ओर बढ़ रहे बदलाव के लिए नवाचार, निवेश और सहयोग की आवश्यकता है। भारत और इटली नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर हाइड्रोजन तकनीक, तथा स्मार्ट ग्रिड से लेकर मजबूत बुनियादी ढांचे तक कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं।

ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात का वैश्विक केंद्र बनने की भारत की पहल अपार संभावनाएं रखती है। यह इटली की नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना में उन्नत तकनीक और यूरोप के लिए ऊर्जा प्रवेश द्वार के रूप में उसकी रणनीतिक भूमिका के साथ पूरी तरह मेल खाती है।इस संदर्भ में भारत की अगुवाई वाली प्रमुख पहलों- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (जीबीए) में अन्य देशों के साथ हमारा सहयोग भी बेहद महत्वपूर्ण है।

भौतिक, डिजिटल और मानवीय संपर्क ही वह कड़ी है जो हमें एक-दूसरे से जोड़ती है। भारत और इटली दोनों वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों-इंडो-पैसिफिक और भूमध्यसागर के केंद्र में स्थित हैं। अब इन क्षेत्रों को अलग-अलग नहीं, बल्कि आपस में जुड़े हुए क्षेत्रों के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, हम एक नए इंडो-मैडिटेरेनियन क्षेत्र के उभरने को देख रहे हैं, जो व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, डेटा और विचारों का एक महत्वपूर्ण गलियारा बन रहा है और हिंद महासागर को यूरोप से जोड़ता है।इसी आपस में जुड़े हुए क्षेत्र में हमारा संबंध स्वाभाविक रूप से एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित होता है- ऐसी साझेदारी, जो दो महाद्वीपों को जोड़ती है और नई वैश्विक परिस्थितियों को आकार देती है।

इस संदर्भ में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) एक ऐसी दूरदर्शी योजना है, जिसका उद्देश्य आधुनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे, डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा प्रणालियों और मजबूत सप्लाई चेन के माध्यम से हमारे क्षेत्रों को जोड़ना है। भारत और इटली अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

हम अपने साझा चुनौतियों का समाधान दोनों देशों के गहरे संबंधों और लंबे सांस्कृतिक जुड़ाव के आधार पर कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में 卐धर्म卐 का विचार उस जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है, जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। वहीं वसुधैव कुटुंबकम्-अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है का सिद्धांत आज के आपस में जुड़े डिजिटल युग में और भी अधिक प्रासंगिक लगता है।

ये मूल्य इटली की मानवतावादी परंपरा से भी मेल खाते हैं, जिसकी जड़ें पुनर्जागरण काल में हैं। यह परंपरा हर व्यक्ति की गरिमा और संस्कृति की उस शक्ति पर जोर देती है, जो समाजों और लोगों को एकजुट कर सकती है। इसलिए हमारी साझा दृष्टि का उद्देश्य लोगों को केंद्र में रखते हुए भारत-इटली साझेदारी को मजबूत, आधुनिक और भविष्य उन्मुख आधार प्रदान करना है।

कार पर सस्ता, शिक्षा ऋण पर ब्याज दर ज्यादा क्यों

- डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा को हमेशा राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है। हम अक्सर कहते हैं कि युवा देश का भविष्य हैं, शिक्षा समाज की रीढ़ है और ज्ञान ही विकास का आधार है। लेकिन जब व्यवहारिक व्यवस्था को देखा जाता है तो तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। विडंबना यह है कि आज भारत में कार खरीदना आसान हो रहा है लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करना लगातार कठिन और महँगा होता जा रहा है। बैंक आपको नई कार खरीदने के लिए आकर्षक ब्याज दरों पर तुरंत ऋण देने को तैयार मिल जाएंगे, परंतु वही बैंक जब किसी विद्यार्थी को शिक्षा ऋण देते हैं तो ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, नियम कठोर हो जाते हैं और भविष्य को जोखिम मान लिया जाता है। यह स्थिति केवल बैंकिंग प्रणाली की तकनीकी समस्या नहीं बल्कि हमारी सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न भी है।

आज भारत में उच्च शिक्षा का खर्च सामान्य परिवारों के सामर्थ्य से बाहर होता जा रहा है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, निजी विश्वविद्यालयों की पढ़ाई या विदेश में शिक्षा—हर क्षेत्र में फीस लाखों में पहुँच चुकी है। मध्यमवर्गीय परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वर्षों की बचत लगा देते हैं, गहने बेचते हैं, भविष्य निधि तोड़ते हैं, फिर भी शिक्षा ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। दुखद स्थिति यह है कि जिस शिक्षा से एक युवा का भविष्य बनना है, उसी पर सबसे अधिक ब्याज का बोझ लाद दिया जाता है। कार लोन की ब्याज दरें कई बार शिक्षा ऋण से कम होती हैं। अर्थात एक उपभोक्ता वस्तु खरीदना शिक्षा प्राप्त करने से सस्ता पड़ता है। यह केवल आर्थिक असंतुलन नहीं बल्कि सामाजिक सोच की भी त्रासदी है।

बैंकिंग व्यवस्था का तर्क यह होता है कि कार लोन सुरक्षित होता है क्योंकि वाहन बैंक के लिए गिरवी संपत्ति का काम करता है। यदि ऋण लेने वाला व्यक्ति भुगतान न करे तो कार जब्त की जा सकती है। लेकिन शिक्षा ऋण में बैंक के पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती। वहाँ केवल छात्र की योग्यता, उसकी डिग्री और उसका भविष्य होता है। इसलिए बैंक इसे जोखिमपूर्ण निवेश मानते हैं। यह तर्क बैंकिंग दृष्टि से भले सही प्रतीत हो लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यंत संकीर्ण है। किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा निवेश उसकी युवा पीढ़ी होती है। एक छात्र जब डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, शोधकर्ता या प्रशासक बनता है तो उसका लाभ केवल व्यक्तिगत नहीं होता, पूरा समाज उससे लाभान्वित होता है। ऐसे में शिक्षा ऋण को केवल व्यापारिक उत्पाद की तरह देखना दूरदर्शिता नहीं कहलाएगा।

वर्तमान समय में शिक्षा ऋण केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि मानसिक दबाव का कारण भी बनता जा रहा है। लाखों विद्यार्थी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही ईएमआई और ब्याज की चिंता में घिर जाते हैं। नौकरी मिलने से पहले ही कर्ज का भय उन्हें परेशान करने लगता है। कई छात्र अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार करियर चुनने के बजाय केवल अधिक वेतन वाली नौकरियों की ओर इसलिए भागते हैं ताकि ऋण चुका सकें। परिणामस्वरूप शोध, अध्यापन, साहित्य, सामाजिक सेवा और कला जैसे क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं की संख्या घटती जा रही है। समाज धीरे-धीरे केवल वेतन आधारित सफलता का समर्थक बनता जा रहा है।

इस समस्या का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय मध्यम वर्ग पर पड़ता है। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार महँगी शिक्षा का खर्च आसानी से उठा लेते हैं। गरीब वर्ग के लिए सरकार की कुछ योजनाएँ और छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं। लेकिन सबसे अधिक संघर्ष उस वर्ग को करना पड़ता है जो 卐गरीब卐 की श्रेणी में नहीं आता, फिर भी लाखों रुपये की फीस वहन करने में सक्षम नहीं होता। ऐसे परिवारों के लिए शिक्षा ऋण मजबूरी बन जाता है। एक पिता पूरी जिंदगी की कमाई बेटे या बेटी की पढ़ाई में लगा देता है, इस उम्मीद के साथ कि शिक्षा भविष्य को सुरक्षित करेगी। लेकिन जब उसी शिक्षा पर भारी ब्याज लग जाता है, तो वह सपना धीरे-धीरे आर्थिक बोझ में बदलने लगता है।

आज भारत में शिक्षा का निजीकरण तेजी से बढ़ा है। सरकारी संस्थानों की सीमित सीटों के कारण लाखों छात्रों को निजी कॉलेजों का रुख करना पड़ता है। वहाँ फीस इतनी अधिक होती है कि सामान्य परिवारों के लिए बिना ऋण के पढ़ाई संभव नहीं रह जाती। कई बार छात्र केवल फीस और ब्याज के कारण अपने सपनों के संस्थान छोड़ देते हैं। प्रतिभा आर्थिक क्षमता के सामने हार जाती है। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज के लिए चिंताजनक है। यह भी विचारणीय है कि आज के समय में शिक्षा केवल व्यक्तिगत प्रगति का माध्यम नहीं रही बल्कि आर्थिक और सामाजिक अस्तित्व की आवश्यकता बन चुकी है। बिना उच्च शिक्षा के बेहतर रोजगार प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में यदि शिक्षा ही महँगी और ऋण बोझिल होगा तो सामाजिक असमानता और बढ़ेगी। जो परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वे आगे निकल जाएंगे, जबकि सीमित साधनों वाले प्रतिभाशाली छात्र पीछे छूटते चले जाएंगे। यह केवल व्यक्ति की हानि नहीं होगी बल्कि देश अपनी संभावित प्रतिभाओं को खो देगा। भारत सरकार को इस दिशा में गंभीर और दीर्घकालिक कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले शिक्षा ऋण की ब्याज दरों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। यदि सरकार वाहन उद्योग, रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक नीतियाँ बना सकती है तो शिक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्र के लिए अलग वित्तीय नीति क्यों नहीं बनाई जा सकती? शिक्षा ऋण पर ब्याज न्यूनतम होना चाहिए और पढ़ाई पूरी होने तक ब्याज स्थगन की व्यवस्था व्यापक स्तर पर लागू की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त रोजगार मिलने तक ऋण पुनर्भुगतान में लचीलापन होना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में कई छात्रों पर डिग्री पूरी होते ही ईएमआई का दबाव शुरू हो जाता है, जबकि नौकरी मिलने में समय लग सकता है। यह मानसिक तनाव युवाओं की ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों को प्रभावित करता है। यदि सरकार और बैंक छात्रों को कुछ वर्षों का व्यावहारिक समय दें तो वे अपने करियर को अधिक स्थिरता के साथ शुरू कर पाएंगे। शिक्षा ऋण के साथ करियर आधारित सहायता मॉडल भी विकसित किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र शोध, अध्यापन, सामाजिक सेवा या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना चाहता है तो उसके ऋण में विशेष छूट दी जा सकती है। इससे समाज के आवश्यक लेकिन कम वेतन वाले क्षेत्रों में भी प्रतिभाशाली युवाओं का आकर्षण बना रहेगा। दुनिया के कई विकसित देशों में शिक्षा को सामाजिक निवेश माना जाता है। वहाँ सरकारें छात्रों को कम ब्याज पर ऋण, छात्रवृत्ति और आय आधारित पुनर्भुगतान जैसी सुविधाएँ देती हैं। भारत में भी यदि हम विश्वगुरु बनने की कल्पना करते हैं तो हमें युवाओं को कर्ज के भय से मुक्त करना होगा। केवल भाषणों और नारों से ज्ञान आधारित समाज नहीं बनता, उसके लिए व्यवहारिक आर्थिक समर्थन भी आवश्यक होता है।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

अब एआई से जानें एंटीबायोटिक्स कारगर है या नहीं

अमेरिका का रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) भारत के साथ साझेदारी कर यह पड़ताल कर रहा है कि एआई-संचालित तौरतरीकों से रोगाणुओं की प्रतिरोध क्षमता का किस तरह तेजी से पता लगाया जा सकता है और इसका मुकाबला किया जा सकता है।

कृत्तिका शर्मा

रोगाणुओं की प्रतिरोध क्षमता के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा खतरा अक्सर वही होता है, ज तुरंत दिखाई नहीं देता। एक मरीज़ संक्रमण के साथ आता है, और डॉक्टर सबसे संभावित कारण के आधार पर इलाज शुरू कर देता है। लेकिन बैक्टीरिया पहले से ही उन मानक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं, जो मरीज़ को दी जा रही हैं। इस प्रतिरोध की पुष्टि करने में कई दिन लग सकते हैं, और जब तक डॉक्टर प्रयोगशाला की रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, संक्रमण तेज़ी से फैलता रह सकता है। यही खामोश अनिश्चितता रोगाणुओं की प्रतिरोध क्षमता, या एएमआर, को इतना खतरनाक बनाती है। यह केवल एक और बीमारी नहीं है। यह आधुनिक चिकित्सा की बुनियाद को ही कमज़ोर कर देता है, जिससे सामान्य संक्रमणों का इलाज करना कठिन हो जाता है। यह ऐसी चुनौती भी है, जिसके लिए बेहतर उपकरण, तेज़ी से कार्रवाई और मजबूत साझेदारियों की आवश्यकता होती है। यहीं पर डॉ. एशले स्टिचिन्स्की की भूमिका आती है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ और यू.एस. सेंटर्स फ़ॉर डिज़ीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) में मेडिकल ऑफिसर डॉ. स्टिचिन्स्की, एम्बेसी साइंस फेलोज़ प्रोग्राम के तहत भारत आए, ताकि यह समझा जा सके कि अमेरिका रोगाणुओं की प्रतिरोध क्षमता (एएमआर) का आकलन करने और उससे निपटने के क्षेत्रीय प्रयासों में किस प्रकार सहयोग कर सकता है। उनका कार्य वैश्विक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुरक्षा और नई खोजों के मिलन बिंदु पर है, विशेष रूप से तब, जब अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को दवा- प्रतिरोधी संक्रमणों का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाने, निगरानी करने और उनसे निपटने के औजार के रूप में आगे बढ़ा रहा है। भारत में डॉ. स्टिचिन्स्की की भूमिका यह पहचानना है कि स्थानीय प्राथमिकताएँ क्या हैं और कहाँ कमियाँ हैं, तथा कहाँ अमेरिका के साथ सहयोग सार्थक बदलाव ला सकता है। राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ पहले से मौजूद हैं, लेकिन तेज़ निदान, मजबूत निगरानी और बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकने वाले तकनीकी समाधानों की आवश्यकता अभी भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है। वैश्विक प्राथमिकता रोगाणुओं की प्रतिरोध क्षमता के बढ़ते स्तर ने इसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया है। वर्षों तक स्वास्थ्य विशेषज्ञ एचआईवी, मलेरिया और तपेदिक को बिग थ्री कहते रहे, क्योंकि हर वर्ष इनसे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती थी। अब रोगाणुओं की प्रतिरोध क्षमता यानी एएमआर भी उसी श्रेणी में आ गया है। डॉ. स्टिचिन्स्की बताती हैं, पिछले कुछ वर्षों में, जब हम अधिक ठोस आंकड़े एकत्र करने में सक्षम हुए हैं, तब हमें यह समझ में आया है कि रोगाणुओं की प्रतिरोध क्षमता भी उसी स्तर पर है, जिससे हर वर्ष दस लाख से अधिक लोगों की मौत हो रही है। लेकिन एएमआर केवल इसलिए खतरा नहीं है कि यह सीधे तौर पर बड़ी संख्या में मौतों का कारण बनता है। यह इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह उन चिकित्सीय उपकरणों और उपचार प्रणालियों को कमजोर कर देता है, जिन पर स्वास्थ्य सेवाओं के अनेक अन्य रूप निर्भर करते हैं। वह कहती हैं, आधुनिक चिकित्सा में हम जो कुछ भी करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि एंटीबायोटिक्स संक्रमणों का प्रभावी ढंग से इलाज कर सकें। इसमें नियमित सर्जरी, कीमोथेरेपी देना और एचआईवी का प्रबंधन जैसी चीजें शामिल हैं। ये सभी प्रभावी एंटीबायोटिक्स पर निर्भर हैं। यदि यह क्षमता समाप्त हो जाती है, तो यह उस स्वास्थ्य सेवा के बड़े हिस्से को कमजोर कर देगा, जिसे हम आवश्यक मानते हैं। यही कारण है कि एएमआर भारत और अमेरिका दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह केवल स्वास्थ्य संबंधी चुनौती नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थागत चुनौती भी है—जो तैयारी, आर्थिक स्थिरता और स्वास्थ्य सेवाओं में जनता के विश्वास को प्रभावित करती है। तेज़ी से पहचान एएमआर की सबसे कठिन बातों में से एक यह है कि यह खुद को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता। एक प्रतिरोधी संक्रमण शुरुआत में किसी सामान्य संक्रमण जैसा ही दिख सकता है। अंतर अक्सर प्रयोगशाला परीक्षण के बाद ही स्पष्ट होता है, और इस प्रक्रिया में समय लगता है। यह पुष्टि करने के लिए कि कोई बैक्टीरिया प्रतिरोधी है या नहीं, प्रयोगशालाओं को सामान्यतः उस जीवाणु को विकसित करना पड़ता है और विभिन्न एंटीबायोटिक्स के खिलाफ उसका परीक्षण करना पड़ता है। डॉ. स्टिचिन्स्की कहती हैं, इसमें आमतौर पर कई दिन लगते हैं, और इस बीच आपके पास एक ऐसा मरीज़ होता है, जो इलाज मिलने की अपेक्षा कर रहा होता है। एएमआर से निपटने में यह एक निरंतर चुनौती बनी हुई है- ऐसे तेज़ निदान उपकरणों तक पहुंच, जो आपको बता सकें कि आप किससे जूझ रहे हैं और वह किन दवाओं के प्रति संवेदनशील है। निदान संबंधी यही कमी उन प्रमुख कारणों में से एक है, जिनकी वजह से अमेरिका एआई- संचालित तरीकों में इतना अधिक निवेश कर रहा है। एआई वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को देरी से पुष्टि से आगे बढ़कर प्रारंभिक पूर्वानुमान तक पहुँचने में मदद कर रहा है। डॉ. स्टिचि स्की

कहती हैं, निदान के क्षेत्र में एआई, विशेष रूप से मशीन लर्निंग, का उपयोग व्यक्तिगत बैक्टीरियल कोशिकाओं को देखने और एंटीबायोटिक्स के संपर्क में आने पर उनके व्यवहार को बहुत प्रारंभिक चरण में समझने के लिए किया जा रहा है, ताकि प्रतिरोध का अनुमान लगाया जा सके। यानी दिनों तक इंतजार करने के बजाय, आपको मिनटों या घंटों में परिणाम मिल सकता है। वह एआई के एक अन्य व्यावहारिक उपयोग की ओर भी संकेत करती हैं- चिकित्सकों को यह निर्णय लेने में मदद करना कि एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता है भी या नहीं। उदाहरण के लिए, एआई बैक्टीरिया की उन विशेषताओं की पहचान करने में मदद कर सकता है, जो विभिन्न बैक्टीरिया में समान रूप से मौजूद रहती हैं, ताकि आप शुरुआत में ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकें- क्या यह वायरल है या बैक्टीरियल, और क्या मुझे एंटीबायोटिक देनी चाहिए या नहीं? भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पैमाना और गति दोनों महत्वपूर्ण हैं, ऐसी प्रगति सार्थक बदलाव ला सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव एएमआर के खिलाफ लड़ाई में एआई की भूमिका केवल निदान तक सीमित नहीं है। डॉ. स्टिचिन्स्की यह भी बताती हैं कि एआई का उपयोग संक्रमण के रुझानों की निगरानी, संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण डेटा के विश्लेषण, और यहाँ तक कि नए एंटीबायोटिक्स की खोज को तेज़ करने के लिए भी किया जा रहा है। वह कहती हैं, कई कंपनियाँ नए एंटीबायोटिक्स विकसित करने के लिए एआई-आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही हैं। उनमें से कुछ कुछ ही घंटों में लाखों यौगिकों की जांच कर संभावित लक्ष्यों की पहचान कर सकती हैं। एक अन्य आशाजनक विकास उपचार संबंधी निर्णयों को मरीज के अनुसार अधिक सटीक बनाने से जुड़ा है। कुछ शोधकर्ता बड़े लैंग्वेज मॉडल का उपयोग कर व्यक्तिगत एंटीबायोग्राम विकसित करने में सक्षम हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधी संक्रमणों के संभावित जोखिम का वर्गीकरण कर सकते हैं, ताकि अंतिम निदान का इंतजार करते समय एंटीबायोटिक्स अधिक सटीक रूप से निर्धारित की जा सकें। फिर भी, इस क्षेत्र का अधिकांश काम अभी शुरुआती चरण में है। वह कहती हैं, हम जानते हैं कि अक्सर किसी तकनीक के विकास और उसके उस ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचने के बीच अंतर होता है, जहाँ उसकी वास्तव में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यही व्यावहारिक दृष्टिकोण उनके संदेश को प्रभावशाली बनाता है। अमेरिकी नेतृत्व केवल शक्तिशाली उपकरण विकसित करने तक सीमित नहीं है। यह भरोसेमंद साझेदारियाँ बनाने, व्यवस्थाओं को मज़बूत करने और संभावनाशील तकनीकों को व्यापक सार्वजनिक लाभ तक पहुँचाने में मदद करने के बारे में भी है। इसमें कार्ब-एक्स जैसे सार्वजनिक-निजी प्रयास शामिल हैं, जो उदाहरण हैं कि किस प्रकार अमेरिका ने नए निदान और उपचार पद्धतियों के शुरुआती विकास में मदद दी है, जिनमें नए एआई प्रयोग भी शामिल हैं, जिसमें भारत के साझेदारों को मदद शामिल है। भारत की भूमिका डॉ. स्टिचिन्स्की की वर्तमान फेलोशिप का उद्देश्य नेपाल और भारत में हितधारकों के साक्षात्कार सहित 80 से अधिक स्रोतों से जानकारी एकत्र करना है, ताकि यह समझा जा सके कि अमेरिका मौजूदा राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार सहयोग कर सकता है। वह भारत को विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानती हैं, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक क्षमता और जमीनी स्तर की प्रासंगिकता दोनों मौजूद हैं। वह कहती हैं, मुझे लगता है कि भारत तकनीकी और सूक्ष्मजीवविज्ञान दोनों क्षेत्रों में योगदान देने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि जिन रोगजनकों को लेकर हम सबसे अधिक चिंतित हैं, उनमें से कई इसी क्षेत्र से आते हैं।

आईपीएल 2026 प्लेऑफ टिकटों की बिक्री 20 मई से शुरू, बीसीसीआई ने जारी किया कार्यक्रम

एजेंसी
नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मुकाबलों के टिकटों की बिक्री को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड ने घोषणा की है कि नॉकआउट चरण के मैचों के टिकट 20 मई से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। जोमैटो द्वारा जिले में टिकट वितरण के लिए आधिकारिक तौर पर एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। बीसीसीआई के अनुसार, टिकटों की बिक्री चरणबद्ध तरीके से की जाएगी ताकि प्रशंसकों को बेहतर सुविधा मिल सके। साथ ही कुछ श्रेणी के कार्डधारकों को शुरुआती बुकिंग का विशेष अवसर भी दिया जाएगा। टिकट बिक्री कार्यक्रम के तहत क्वालिफायर-1 और एलिमिनेटर मुकाबलों के लिए विशेष प्राथमिकता अवधि 20 मई से शुरू होगी। क्वालिफायर-1 मुकाबला एचपीसीए स्टेडियम में 26 मई को खेला जाएगा, जबकि एलिमिनेटर मैच 27 मई को न्यू चंडीगढ़ स्थित स्टेडियम में आयोजित होगा। वहीं क्वालिफायर-2 और फाइनल के लिए प्राथमिक बुकिंग सुविधा 22 मई से उपलब्ध होगी। क्वालिफायर-2 मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा, जबकि आईपीएल 2026 का फाइनल 31 मई को नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह लगातार दूसरे वर्ष होगा जब यह मैदान आईपीएल फाइनल की मेजबानी करेगा।

भारत अंडर-18 हॉकी टीम की शानदार वापसी, ऑस्ट्रेलिया को 6-3 से हराकर सीरीज बराबर की

भोपाल। भारतीय अंडर-18 पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया अंडर-18 टीम को 6-3 से हराकर चार मैचों की सीरीज में दमदार वापसी की। भोपाल स्थित उदय दास मेहता (भाई जी) केंद्रीय साई केंद्र में खेले गए मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए मैच पर शुरू से अंत तक पकड़ बनाए रखी। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में बराबरी हासिल कर ली और अब अंतिम मुकाबला निर्णायक बन गया है। भारतीय टीम ने शुरुआती मिनटों से ही तेज खेल दिखाया और पहले हाफ में ऑस्ट्रेलियाई टीम पर लगातार दबाव बनाया। भारत के लिए आकाश दीप ने 10वें मिनट में गोल कर टीम का खाता खोला। इसके तुरंत बाद शाहरुख अली ने 14वें मिनट में गोल दागकर बढ़त को मजबूत किया। दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने आक्रामकता और बढ़ा दी। कप्तान केतन कुशवाहा ने 25वें मिनट में गोल किया, जबकि अगले ही मिनट में रोमित पाल ने स्कोरबोर्ड पर एक और गोल जोड़ दिया।

विश्व एवं पैरा आर्मरेसलिंग चैम्पियनशिप-2026 की मेजबानी करेगा दिल्ली

मुंबई। भारतीय आर्मरेसलिंग के लिए ऐतिहासिक क्षण में दिल्ली को 47वीं विश्व आर्मरेसलिंग एवं 28वीं पैरा आर्मरेसलिंग चैम्पियनशिप-2026 की मेजबानी सौंपी गई है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक दिल्ली के लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में आयोजित होगी। इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में 75 से अधिक देशों के करीब 2000 खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। इसे आर्मरेसलिंग जगत के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में से एक माना जा रहा है। गौरतलब है कि इसी लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में 2025 एशियाई आर्मरेसलिंग एवं पैरा आर्मरेसलिंग चैम्पियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न वर्गों में कुल 176 पदक जीतकर महाद्वीपीय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया था। विश्व आर्मरेसलिंग महासंघ के अध्यक्ष असेन हाजीतोदोरोव ने कहा, 'मैं दुनिया के सभी मजबूत खिलाड़ियों को दिल्ली में होने वाली विश्व चैम्पियनशिप के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शानदार आयोजन और भारत में अपने मित्रों की बेहतरीन मेजबानी की उम्मीद है। आइए, हम सब मिलकर दिल्ली में इस प्रतियोगिता को यादगार बनाएं।'

अर्शदीप सिंह के चोटिल होने की खबर को पंजाब किंग्स ने बताया अफवाह, कहा- वह पूरी तरह से फिट

नई दिल्ली। पंजाब किंग्स ने अपने प्रमुख तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की फिटनेस को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि वह पूरी तरह फिट हैं और लगातार टीम के साथ अभ्यास कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक बयान में कहा, 'कुछ रिपोर्टों के विपरीत हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे प्रमुख तेज गेंदबाज और टीम के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह पूरी तरह फिट हैं। वह नियमित रूप से टीम के साथ प्रशिक्षण कर रहे हैं। टीम प्रबंधन उनकी प्रगति से बेहद संतुष्ट है और वह टूर्नामेंट के अहम मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार हैं।' पंजाब किंग्स ने आगे कहा कि नेट्स में अर्शदीप की ऊर्जा, लय और प्रतिबद्धता काफी उत्साहजनक रही है और टीम को भरोसा है कि वह आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद में घिरे अर्शदीप

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अर्शदीप सिंह ने पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस मैच से पहले मुंबई बल्लेबाज तिलक वर्मा के साथ एक स्नैपचैट स्टोरी साझा की। इस पोस्ट में उन्होंने तिलक को 'अंधेरा' कहा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें नस्लभेदी टिप्पणी करने के आरोपों का सामना करना पड़ा। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर भारी आलोचना शुरू हो गई, जिसके चलते पंजाब किंग्स को सार्वजनिक रूप से सफाई देनी पड़ी। पंजाब किंग्स के हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड्रयू लीपस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्शदीप का बचाव करते हुए कहा कि खिलाड़ी का व्यवहार ड्रेसिंग रूम में सामान्य बना हुआ है।

आरोन हार्डी बने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नए शेफील्ड शील्ड कप्तान

एजेंसी
नई दिल्ली। ऑलराउंडर आरोन हार्डी को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। वह आगामी 2026-27 सीजन से सैम व्हाइटमैन की जगह टीम की कमान संभालेंगे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की रेड-बॉल टीम इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है। तीन बार शेफील्ड शील्ड खिताब जिताने वाले मुख्य कोच एडम वोग्स के पद छोड़ने के बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर ब्यू कैसन को शेफील्ड शील्ड और वनडे कप टीमों का नया मुख्य कोच बनाया गया है। कैसन इससे पहले लंबे समय तक टीम के बल्लेबाज़ी कोच रहे थे। सैम व्हाइटमैन ने एडम वोग्स के कार्यकाल में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए 38 शेफील्ड शील्ड मैचों में कप्तानी की। उनकी

कप्तानी में टीम ने 2022-23 और 2023-24 में लगातार दो बार खिताब जीता था। वह जॉन इनवरैरिटी, ग्रेम वुड और टॉम मूडी के बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को एक से अधिक शील्ड जिताने वाले चौथे कप्तान बने थे।

हालांकि, व्हाइटमैन ने इंग्लैंड की काउंटी टीम यॉर्कशायर के साथ लंबी अवधि का अनुबंध किया है और दोहरी नागरिकता के कारण वह अब विदेशी खिलाड़ी के रूप में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे। इसी कारण टीम प्रबंधन ने नई नेतृत्व व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया।27 वर्षीय आरोन हार्डी को लंबे समय से भविष्य का कप्तान माना जा रहा था। उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया-ए टीम की कप्तानी की थी, जबकि 2025 में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भी टीम का नेतृत्व संभाला था। इसके अलावा, 2023-24 बिग बैश लीग में एश्टन टर्नर की गैरमौजूदगी में उन्होंने पर्थ स्कॉर्चर्स की कप्तानी भी की थी। कप्तान बनाए जाने पर हार्डी ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ओर से जारी एक बयान में कहा, 'वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड टीम की कप्तानी मिलना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। यह टीम मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे पास शानदार संस्कृति और बेहतरीन खिलाड़ियों का समूह है। मैं ब्यू कैसन और पूरी टीम के साथ नए सीजन में काम करने को लेकर उत्साहित हूं।' उन्होंने आगे कहा, 'मैंने पिछले कुछ वर्षों में टीम के नेताओं और खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं अपनी शैली में नेतृत्व करते हुए ऐसा माहौल बनाना चाहता हूं, जहां पूरी टीम बेहतर प्रदर्शन कर सके।'

असम को मिलेगा अपना प्रीमियर लीग, अगस्त में होगा एपीएल का आयोजन

एजेंसी
गुवाहाटी। तमिलनाडु, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तर्ज पर अब असम का भी अपना प्रीमियर लीग होगा, जिसका नाम असम प्रीमियर लीग(एपीएल) है और इसका आयोजन आगामी अगस्त माह में किया जाएगा। यह लीग इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तर्ज पर आयोजित होगी।यह जानकारी देते हुए बीसीसीआई सचिव देवजीत लोन सैकिया ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एपीएल राज्य के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच साबित होगा। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट को पेशेवर ढंग से आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस लीग के माध्यम से असम में क्रिकेट प्रतिभाओं को नई पहचान मिलेगी तथा राज्य में खेल अवसंरचना और क्रिकेट संस्कृति को भी बढ़ावा

मिलेगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में असम प्रीमियर लीग पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण क्रिकेट आयोजन बनकर उभरेगा।

'विकेट आसान नहीं था, इसलिए अंत तक टिके रहना जरूरी था' – ईशान किशन

एजेंसी
चेन्नई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बल्लेबाज़ ईशान किशन ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ सोमवार रात शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। चेन्नई की धीमी और चुनौतीपूर्ण पिच पर 47 गेंदों में 70 रन बनाने वाले ईशान ने मैच के बाद कहा कि विकेट आसान नहीं था और ऐसे में उनकी कोशिश अंत तक बल्लेबाज़ी करने की थी।

ईशान किशन ने बताया कि विकेटकीपिंग करते समय ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि 180 रन का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। मैच के बाद उन्होंने कहा, 'जब मैं विकेटकीपिंग कर रहा था, तभी मुझे लगा कि यह विकेट बिल्कुल आसान नहीं है। खासकर जब स्पिनर गेंदबाज़ी कर रहे थे और स्लोअर गेंदें प्रभावी हो रही थीं। मुझे महसूस हुआ कि इस लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल रहेगा। ऐसे में नंबर-3 बल्लेबाज़ होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अंत तक खेलूं और मैच खत्म करके आऊं।' ईशान

तीसरे ओवर में बल्लेबाज़ी करने उतरे और लगभग अंत तक क्रीज पर डटे रहे। जब हैदराबाद को जीत के लिए केवल 6 रन चाहिए थे, तब वह आउट हुए। उनकी इस पारी ने टीम की जीत की नींव रखी।

उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ खुद पर भरोसा बनाए रखने की बात थी। कई बार परिस्थितियां कठिन होती हैं, लेकिन आपको खुद पर शक नहीं करना चाहिए। मैं बस चीजों को सरल रखना चाहता था और जितने ज्यादा ओवर संभव हो सके बल्लेबाज़ी करना चाहता था।' ईशान ने आगे कहा कि बाएं हाथ के बल्लेबाज़ होने के कारण गेंदबाज़ों के लिए लगातार सही एरिया में गेंदबाज़ी करना आसान नहीं होता। हेनरिक क्लासेन ने भी मैच के बाद पिच को चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, 'शुरुआत में मैंने कुछ गेंदें रोकीं, लेकिन फिर खुद से कहा कि मैं इस तरह बल्लेबाज़ी नहीं कर सकता। मुझे आक्रामक खेलना होगा और आज वह रणनीति सफल रही।' क्लासेन ने चेन्नई की पिच को लेकर कहा, 'पिच नीचे रह रही थी। जब हम गेंदबाज़ी कर रहे थे तो कटर्स काफी धीमे हो रहे थे और गेंद नीचे रह रही थी। बल्लेबाज़ी आसान नहीं थी, लेकिन यह चेन्नई की बेहतर पिचों में से एक थी।'

ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे कप्तान साबित होंगे, लेकिन बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत : स्टीफन फ्लेमिंग

एजेंसी
चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का समर्थन करते हुए कहा है कि वह भविष्य में फ्रेंचाइजी के लिए बेहतरीन कप्तान साबित होंगे, हालांकि इस सीजन में उनकी बल्लेबाजी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही है। फ्लेमिंग ने कहा कि ऋतुराज को बल्लेबाजी में और बेहतर प्रदर्शन करना होगा। फ्लेमिंग ने मैच के बाद कहा, 'मुझे लगता है कि ऋतुराज और बेहतर कर सकते हैं। वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं। वह शीर्ष क्रम के शानदार बल्लेबाज रहे हैं। लेकिन इस सीजन में उन्होंने अपने करियर के मुताबिक न तो उतने रन बनाए हैं और न ही उसी गति से रन बनाए हैं। यह ऐसी चीज है जिस पर वह जरूर काम करेंगे।' सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई में खेले गए मुकाबले में सीएसके को एक ओवर शेष रहते पांच विकेट से हरा दिया। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स अब लगातार तीसरे सीजन प्लेऑफ में पहुंचने से चूकती नजर आ रही है।ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी,

खासकर पावरप्ले में धीमी शुरुआत, इस सीजन लगातार चर्चा का विषय रही है। हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी वह शुरुआती छह ओवर में 11 गेंदों पर सिर्फ 9 रन ही बना सके। फ्लेमिंग ने पिछले सीजन की चोट का जिक्र करते हुए कहा, 'कम से कम इस साल वह पूरे समय टीम के साथ थे। पिछले साल चोट के कारण वह उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उस आधार पर उनका आकलन करना उचित नहीं होगा। लेकिन हमने इस टीम और खिलाड़ियों को समझने के लिए पर्दे के पीछे काफी काम किया है।' उन्होंने आगे कहा, 'एमएस धोनी जैसे महान कप्तान के लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संभालने के बाद नए कप्तान के लिए यह बदलाव आसान नहीं होता। इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ऋतुराज अच्छा काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों के बीच उन्हें काफी सम्मान मिलता है। वह लगातार सीख रहे हैं और उसे मैदान पर लागू भी कर रहे हैं। मुझे कोई संदेह नहीं कि भविष्य में वह इस फ्रेंचाइजी के शानदार कप्तान बनेंगे।' एमएस धोनी इस सीजन पहली बार मैच के दिन मैदान पर टीम के साथ नजर आए। अगले सीजन में धोनी के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर फ्लेमिंग ने कहा, 'नहीं, फिलहाल हम इसी सीजन पर ध्यान दे रहे हैं।'

बेंगलुरु में 5वीं राष्ट्रीय दिव्यांग एलीट क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ

एजेंसी
बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य दिव्यांग क्रिकेट संघ के तत्वावधान में 5वीं राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग एलीट क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच हुआ। देशभर की शीर्ष टीमें इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, जिससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए राष्ट्रीय मंच मिल रहा है। उद्घाटन समारोह में पीसीसीएआई अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया, डीसीसीआई एवं पीसीसीएआई महासचिव रविकांत चौहान, पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण, कर्नाटक दिव्यांग क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हेमचंद्र और सचिव संतोष गौड़ा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के साथ प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर डीसीसीआई महासचिव रविकांत चौहान ने कहा कि डीसीसीआई लगातार 24 टीमों के साथ राष्ट्रीय

प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहा है, लेकिन इस वर्ष प्रतियोगिता को अधिक प्रतिस्पर्धी और उच्च गुणवत्ता वाला बनाने के उद्देश्य से शीर्ष 12 टीमों के बीच एलीट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। शेष 12 टीमों के लिए प्लेट ग्रुप प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार करना है। रविकांत चौहान ने बताया कि संगठन खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'मैन ऑफ द सीरीज' पुरस्कार स्वरूप कार और स्कूटर तक दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि डीसीसीआई का लक्ष्य दिव्यांग क्रिकेटरों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करना और उनके खेल स्तर को लगातार बेहतर बनाना है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, टूर्नामेंट और अंतरराष्ट्रीय स्तर की हर आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में दिव्यांग क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। साथ ही उन्होंने सभी प्रायोजकों, सहयोगियों और समर्थकों का आभार व्यक्त किया। पीसीसीएआई अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि उनकी संस्था पिछले 15 वर्षों से दिव्यांग क्रिकेट के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक लगभग 30.36 लाख रुपये की 'मैन ऑफ द मैच' पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था देश की पहली ऐसी संस्था है, जो प्रत्येक 'मैन ऑफ द मैच' विजेता को 11 हजार रुपये प्रदान करती है।

उन्होंने बताया कि अब तक खिलाड़ियों को कुल 87 लाख रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि वितरित की जा चुकी है और भविष्य में भी खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के प्रयास जारी रहेंगे। पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण ने कहा कि पैरालंपिक समिति, डीसीसीआई के साथ मिलकर मिश्रित दिव्यांग क्रिकेट को एशियन पैरा गेम्स और पैरालंपिक खेलों में शामिल कराने की दिशा में काम कर रही है।

फीफा विश्व कप 2026 के लिए ब्राज़ील टीम का ऐलान, नेमार की वापसी

एजेंसी
नई दिल्ली। ब्राज़ील पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कार्लो एंचेलोटी ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए टीम का ऐलान कर दिया। टीम में स्टार फुटबॉलर नेमार की वापसी हुई है, जो 2023 के बाद पहली बार राष्ट्रीय टीम में शामिल हुए हैं। 34 वर्षीय नेमार अपने करियर का चौथा फीफा विश्व कप खेलेंगे। वह ब्राज़ील के लिए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 128 मैचों में 79 गोल किए हैं। रियो डी जेनेरियो के म्यूज़ियम ऑफ टुमॉरो में जब एंचेलोटी ने नेमार का नाम घोषित किया तो वहां मौजूद समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। ब्राज़ील को फीफा विश्व कप 2026 में मोरक्को, हैती और स्कॉटलैंड के साथ ग्रुप में रखा गया है। टीम अपने अभियान की शुरुआत 13 जून को मोरक्को के खिलाफ करेगी।

फीफा विश्व कप 2026 के लिए ब्राज़ील टीम

गोलकीपरः
एलिसन, एडर्सन, वेवर्टन
डिफेंडरः
मार्किन्होस, गेब्रियल मागाल्हाएस, ब्रेमर, लियो परेरा,

डेनिलो, वेस्ले, डगलस सैंटोस, एलेक्स सैंड्रो, इबानेज
मिडफील्डरः
ब्रूनो गुइमारेस, कासेमिरो, डेनिलो एस., लुकास पाक्वेटा, फाबिन्हो
फॉरवर्डः
विनीसियस जूनियर, राफिन्हा, गेब्रियल मार्टिनेली, एंड्रिक, इगोर थियागो, मथियस कुन्हा, नेमार, लुइज हेनरिक, रायन।

मलेशिया मास्टर्स 2026: लक्ष्य सेन पर रहेंगी भारत की निगाहें, सिंधु और सात्विक-चिराग टूर्नामेंट से बाहर

एजेंसी
नई दिल्ली। कुआलालंपुर में आज (मंगलवार) से शुरू हो रहे मलेशिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती की अगुवाई लक्ष्य सेन करेंगे। हालांकि इस बार भारतीय दल में कई बड़े नाम शामिल नहीं हैं। भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी. वी. सिंधु, किदांबी श्रीकांत, युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा ने इस बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 500 प्रतियोगिता से दूरी बनाई है। विश्व रैंकिंग में 11वें स्थान पर मौजूद लक्ष्य सेन के लिए कुआलालंपुर अब तक खास सफल नहीं रहा है। वह मलेशिया मास्टर्स और मलेशिया ओपन में कभी दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ सके हैं। पहले दौर में उनका मुकाबला इंडोनेशिया के युवा

खिलाड़ी मोहम्मद जाकी उबैदिलाह से होगा, जिन्होंने पिछले जूनियर विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। यदि लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं तो उनका सामना दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी क्रिस्टो पोपोव से हो सकता है। पुरुष एकल वर्ग में भारत की ओर से एच. एस. प्रणय, किरण जॉर्ज और थारुन मन्नेपल्ली भी चुनौती पेश करेंगे। प्रणय ने 2023 में इसी टूर्नामेंट का खिताब जीता था, लेकिन इस बार पहले दौर में उनका मुकाबला जापान के छठी वरीयता प्राप्त कोडाई नाराओका से होगा। महिला एकल में भारत की ओर से देविका सिहाग, तन्वी शर्मा, अनमोल खरब, मालविका बंसोड़, ईशारानी बरुआ और तान्या हेमंत हिस्सा लेंगी। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर विशेष नजरें रहेंगी। वह पहले दौर में थाईलैंड की पिचामोन ओपाटनिपुथ से भिड़ेंगी। तन्वी ने पिछले वर्ष यूएस ओपन में इसी खिलाड़ी को हराया था। वहीं, अनमोल खरब भी चर्चा में हैं। पिछले सप्ताह बैंकॉक में उन्होंने चीन की विश्व नंबर चार चेन यू फी के खिलाफ निर्णायक गेम में 11-2 की बढ़त गंवा दी थी। इस बार पहले दौर में उनका सामना डेनमार्क की आठवीं वरीयता प्राप्त लाइन क्जाएर्सफेल्ट से होगा। पुरुष युगल में भारत की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी हरिहरन अम्साकरुनन और एम. आर. अर्जुन ही ड्रॉ में शामिल हैं। पहले दौर में उनका मुकाबला फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी से होगा। महिला युगल में अश्विनी भट्ट-शिखा गौतम तथा रुतुपर्णा पांडा-श्वेतपर्णा पांडा की जोड़ियां उतरेंगी। मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर-रुत्विका गड्डे और आशित सूर्य-अमृता प्रमुथेश की जोड़ियां भारत की चुनौती पेश करेंगी।

स्पेन को बड़ा झटका: लामिन यामाल विश्व कप के पहले मैच से बाहर

एजेंसी
नई दिल्ली। स्पेन फुटबॉल टीम को फीफा विश्व कप 2026 शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा है। स्टार युवा फॉरवर्ड लामिन यामाल हैमस्ट्रिंग चोट के कारण 15 जून को केप वर्डे के खिलाफ होने वाले शुरुआती मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। यह जानकारी 'द एथलेटिक' की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, यामाल अभी पूरी तरह फिट नहीं हो सके हैं और उनके 21 जून को सऊदी अरब के खिलाफ होने वाले दूसरे ग्रुप मुकाबले में खेलने पर भी संशय बना हुआ है। 18 वर्षीय यामाल को यह चोट 22 अप्रैल को एफसी बार्सिलोना की ओर से खेलते हुए सेल्टा वीगो के खिलाफ मैच में लगी थी। उस मुकाबले में पेनल्टी पर गोल करने के दौरान उनकी बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट आ गई थी, जिसके बाद वह क्लब सीजन के बाकी मुकाबलों से बाहर हो गए थे। दूसरी ओर, बार्सिलोना के ही मिडफील्डर फरमिन लोपेज भी चोटिल होकर लगभग पूरे विश्व कप से बाहर हो गए हैं। रियल बेटिस के खिलाफ मैच के पहले हाफ में उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी। स्पेन अपना पहला मुकाबला 15 जून को अमेरिका के अटलांटा में केप वर्डे के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद टीम 21 जून को सऊदी अरब और 26 जून को उरुग्वे से भिड़ेगी। उरुग्वे के खिलाफ यह मुकाबला मेक्सिको के ग्वाडलाहारा में खेला जाएगा।

फीफा की ताजा पुरुष विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद स्पेन अपनी 26 सदस्यीय विश्व कप टीम की घोषणा अगले करेगा।

गौरतलब है कि लामिन यामाल ने यूरो 2024 में शानदार प्रदर्शन कर स्पेन को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। स्पेन के लिए 25 मैचों में उनके नाम 6 गोल दर्ज हैं। वहीं, बार्सिलोना के लिए इस सीजन ला लीगा में 28 मैचों में 16 गोल और सभी प्रतियोगिताओं में 45 मैचों में कुल 24 गोल किए।

आईपीएल 2026 : हैदराबाद ने चेन्नई को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में बनाई जगह

एजेंसी
चेन्नई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने संतुलित खेल का प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य को एक ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम ने नॉकआउट चरण का टिकट हासिल कर लिया, जबकि चेन्नई के लिए अंतिम चार में पहुंचने की राह बेहद कठिन हो गई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। टीम को तेज शुरुआत मिली और बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों में तेजी से रन जोड़े। संजू सैमसन ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों पर 27 रन बनाए और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। इसके बाद कार्तिक शर्मा ने भी तेजी दिखाई और 19 गेंदों पर 32 रन जोड़े। मध्यक्रम में डेवाल्ड ब्रेविस ने पारी को संभालते हुए 27 गेंदों में 44 रन बनाए। उनके साथ शिवम दूबे ने उपयोगी 26 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। हैदराबाद की ओर से कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी में सबसे प्रभावी साबित हुए।

रानी अंडर-18 टीम के साथ शानदार काम कर रही हैं : टिम व्हाइट

एजेंसी
भोपाल। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच टिम व्हाइट ने भारत-ऑस्ट्रेलिया अंडर-18 एक्सपोजर सीरीज़ के दौरान युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। भोपाल में चल रही इस सीरीज़ के दौरान खिलाड़ियों का निरीक्षण करने पहुंचे व्हाइट ने कहा कि अंडर-18 टीम की कोच रानी रामपाल युवा खिलाड़ियों के साथ शानदार काम कर रही हैं। करीब छह सप्ताह पहले बेंगलुरु में भारतीय अंडर-21 महिला टीम की जिम्मेदारी संभालने वाले व्हाइट ने कहा कि जूनियर और सीनियर स्तर के बीच मजबूत तालमेल बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने हॉकी इंडिया के हवाले से कहा, 'मैं भोपाल आकर अंडर-18 खिलाड़ियों को देखने के लिए बेहद उत्सुक था क्योंकि यही हमारे भविष्य की प्रतिभाओं की सीधी पाइपलाइन है। रानी के साथ मेरी शानदार बातचीत और तालमेल रहा है और वह इस युवा टीम के साथ बेहतरीन काम कर रही हैं। व्हाइट ने कहा कि इस टीम में कई 15 और 16 वर्ष की खिलाड़ी हैं, जिनमें शारीरिक और तकनीकी रूप से आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले और दूसरे मैच के बीच खिलाड़ियों में जो सुधार और अनुकूलन देखने को मिला, वह काफी उत्साहजनक है। यह सीरीज़ दोनों देशों के लिए खिलाड़ियों के विकास पर केंद्रित है।' उन्होंने भारतीय हॉकी में अपने शुरुआती अनुभव साझा करते हुए कहा कि हॉकी इंडिया लीग में तमिलनाडु ड्रैगन्स पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में काम करने से उन्हें भारतीय हॉकी को समझने में मदद मिली। व्हाइट ने कहा, 'पिछले छह सप्ताह काफी व्यस्त रहे, लेकिन हमने

शुरुआती चरण में वही हासिल किया जो मैं चाहता था। ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम जैसे देशों में कोचिंग करने के अनुभव के आधार पर मैं मानता हूं कि कोचिंग के मूल सिद्धांत हर जगह समान होते हैं। भाषा की कुछ छोटी बाधाएं हैं, लेकिन हम अनुवाद, व्हाइटबोर्ड और सरल संदेशों की मदद से उन्हें आसानी से दूर कर लेते हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'मेरा पहला लक्ष्य भारतीय जूनियर लड़कियों को आधुनिक और अलग शैली की हॉकी खिलाना है, जिससे उनकी पूरी क्षमता सामने आ सके।' सितंबर में चीन में होने वाले जूनियर महिला एशिया कप को ध्यान में रखते हुए व्हाइट ने कहा कि टीम का लक्ष्य सिर्फ जूनियर स्तर पर पदक जीतना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को सीनियर टीम के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा, 'हमारा अल्पकालिक लक्ष्य सितंबर तक ऐसी मजबूत टीम तैयार करना है जो चीन जैसी एशियाई ताकतों को कड़ी चुनौती दे सके। लेकिन जूनियर कार्यक्रम का असली उद्देश्य खिलाड़ियों में सही आदतें, तकनीकी समझ और खेल शैली विकसित करना है ताकि वे सीनियर टीम में जाकर तुरंत विश्वस्तरीय प्रदर्शन कर सकें।'

भारत का निर्यात वित वर्ष 27 में एक ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीदः पीयूष गोयल

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अगले पांच वर्षों के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है, जबकि वित वर्ष 2027 के लिए कुल निर्यात लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर निर्धारित किया गया है। अमेरिकी टैरिफ विवाद और भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक बाजारों में मौजूद अनिश्चितताओं के बावजूद, वित्त वर्ष 2026 में भारत का कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर 863 अरब डॉलर पर पहुंच गया। मंत्री ने कहा कि यूक्रेन युद्ध और ईरान युद्ध के कारण मध्य पूर्व तनावों से उत्पन्न वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत एक उज्ज्वल पक्ष बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) अब वैश्विक व्यापार के दो-तिहाई से अधिक हिस्से को कवर करते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि ओमान के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता 1 जून से प्रभावी होने की उम्मीद है, जबकि अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते भी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस वर्ष लागू होने की संभावना है।

लिबर्टी म्यूचुअल ने भारत में लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 74 फीसदी की

नई दिल्ली/मुंबई। अमेरिका की बीमा कंपनी लिबर्टी म्यूचुअल इंश्योरेंस ने भारत स्थित अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (एलजीआई) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी है। ये कदम भारतीय बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमा को बढ़ाकर 100 फीसदी किए जाने के बाद उठाया गया है। लिबर्टी म्यूचुअल इंश्योरेंस ने जारी एक बयान में कहा कि उसने भारत में लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (एलजीआई) में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 74 फीसदी कर लिया है। इससे पहले सितंबर 2025 में लिबर्टी म्यूचुअल ने भारतीय इकाई में अपनी हिस्सेदारी 49 फीसदी से बढ़ाकर 55.40 फीसदी की थी। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक पराग वेद ने इस अवसर पर कहा, 'लिबर्टी म्यूचुअल के मजबूत समर्थन के साथ अब हम अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार करने और रिटेल एवं कमर्शियल लाइन सेगमेंट्स में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने की बेहतर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस ऐसे व्यवसाय के निर्माण पर बना हुआ है जो निरंतरता, मजबूती और मजबूत बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित हो। साथ ही ऐसे बाजार के अनुकूल बने रहें जिसकी पहचान ही लगातार हो रहे बदलाव हैं।'

भारतीय शेयर बाजार विभिन्न झटकों को झेलने में सक्षमः तुहिन कांत पांडेय

भुवनेश्वर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव बढ़ा है, लेकिन भारतीय शेयर बाजार 'विभिन्न तरह के झटके झेल पाने' में सक्षम है।पूंजी बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष ने यहां आयोजित 'क्षेत्रीय निवेशक जागरूकता संगोष्ठी' के इतर संवाददाताओं से कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा होने वाले संकट का असर अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट से कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला और कीमतें प्रभावित हुई हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई का जोखिम बढ़ा है। तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि मार्केट रेगुलेटर जल्द ही एआई-आधारित ट्रेडिंग के लिए गाइडलाइंस जारी करेगा। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए अवसर और बढ़ते हुए साइबर जोखिम, दोनों ही लेकर आता है। उन्होंने कहा कि सेबी ट्रेडिंग गतिविधियों में एआई के बढ़ते इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर बाजार आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए उतार-चढ़ाव की स्थिति होना स्वाभाविक है।

मारुति सुजुकी का हरियाणा के खरखौदा प्लांट में उत्पादन शुरू, कुल उत्पादन क्षमता हुई 5 लाख इकाई

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) ने हरियाणा स्थित अपनी खरखौदा विनिर्माण इकाई के दूसरे संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.5 लाख इकाई है। इससे खरखौदा में मारुति की कुल क्षमता बढ़कर पांच लाख इकाई हो गई है। मारुति सुजुकी ने कहा कि नए संयंत्र के शुरू होने के साथ ही गुरुग्राम, मानेसर और खरखौदा (हरियाणा) तथा हंसलपुर (गुजरात) स्थित संयंत्रों में कंपनी की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 26.5 लाख इकाइयों पर हो गई है। कंपनी ने बताया कि पूरी तरह संचालित होने पर खरखौदा संयंत्र मूल कंपनी सुजुकी के सबसे बड़े चार पहिया वाहन विनिर्माण स्थलों में से एक होगा जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 10 लाख वाहन बनाने की होगी।

पेट्रोल और डीजल के रेट में हुई बढ़ोतरी, 86 पैसे पेट्रोल और 83 पैसे डीजल के दाम और बढ़े

एजेंसी

नई दिल्ली। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 83 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दामों में हुए इस बदलाव के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 98.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91.58 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। गौरतलब है कि इससे पहले बीते शुक्रवार, 15 मई को भी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। तब पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर और सीएनजी में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। जिसके बाद विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं समेत राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली थी। तेल-गैस की कीमतों में इजाफा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने फैसले का बचाव किया था। भाजपा नेताओं ने भारत और अन्य देशों में तेल कीमतों में बढ़ोतरी की तुलना की थी। साथ ही, दावा किया था

कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत वह देश रहा जहां आम नागरिकों पर सबसे कम बोझ पड़ा। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा था कि पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने और तेल आपूर्ति बाधित होने के कारण अप्रैल और मई के अधिकांश समय ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बना रहा। इसका असर दुनिया की लगभग हर अर्थव्यवस्था में सीधे पेट्रोल पंपों पर दिखाई दिया। लेकिन भारत इस पूरी तस्वीर में एक अलग और उल्लेखनीय अपवाद बनकर उभरा है। अमित मालवीय ने लिखा था कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 44.5 प्रतिशत बढ़ीं और डीजल की कीमतों में 48.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 54.9 प्रतिशत और डीजल के दाम 44.9 प्रतिशत बढ़े हैं। ब्रिटेन में पेट्रोल की कीमत में 19.2 प्रतिशत और डीजल की कीमत में 34.2 प्रतिशत का इजाफा हुआ। इन देशों के मुकाबले भारत की बात करते हुए भाजपा नेता ने कहा था कि भारत में वृद्धि सबसे कम रही, जहां पेट्रोल की कीमत में 3.2 प्रतिशत और डीजल की कीमत में 3.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया था कि अब जबकि प्रधानमंत्री के करीबी दोस्तों अमेरिका और इजरायल की ओर से पश्चिम एशिया में छेड़े गए युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें बढ़ रही हैं और विधानसभा चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं, सरकार ने पहले वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतें बढ़ाने के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है। इससे महंगाई और बढ़ना तय है।

ईंधन कीमत बढ़ने के बाद भी तेल कंपनियों को रोजाना 750 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा हैः शीर्ष अधिकारी

एजेंसी

नई दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकारी तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) हालिया ईंधन मूल्य वृद्धि के बावजूद अब भी भारी वित्तीय दबाव का सामना कर रही हैं, और कंपनियों को अभी भी प्रतिदिन करीब 750 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल और एलएनजी आयात में लगातार बाधाएं बनी हुई हैं, जिससे पिछले तकरीबन डेढ़ महीने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है। मौजूदा ईंधन आपूर्ति स्थिति पर बोलते हुए शर्मा ने भरोसा दिलाया कि भारत में फिलहाल ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और देश के किसी भी हिस्से में कमी की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा, 'हमारे पास पर्याप्त भंडार है और कहीं भी ईंधन खत्म होने जैसी स्थिति सामने नहीं आई है।' शर्मा ने कहा, 'सरकार और तेल कंपनियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति और सुचारु वितरण सुनिश्चित किया जा सके।' शर्मा के अनुसार, ईंधन मांग के पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब थोक ईंधन बिक्री से अधिक मांग खुदरा पेट्रोल पंपों की ओर शिफ्ट हो रही है, ताकि उपभोक्ताओं को लगातार आपूर्ति मिलती रहे। उन्होंने बताया कि सरकारी तेल कंपनियों को होने वाला दैनिक नुकसान पहले करीब 1,000 करोड़ रुपए था, जो हालिया ईंधन मूल्य वृद्धि के बाद घटकर लगभग 750 करोड़ रुपए प्रतिदिन रह गया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन कंपनियों के लिए किसी राहत पैकेज पर विचार नहीं कर रही है।

एसएफआईओ में यंग प्रोफेशनल समेत 69 पदों पर निकली भर्ती, तुरंत करें आवेदन

एजेंसी

नई दिल्ली। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने कनिष्ठ सलाहकार (जूनियर कंसल्टेंट) और युवा पेशेवर (यंग प्रोफेशनल) के विभिन्न 69 पदों पर अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। पदों का विवरण: एसएफआईओ की ओर से जारी 69 पदों में जूनियर कंसल्टेंट के 37 और यंग प्रोफेशनल के 32 पद शामिल हैं। जूनियर कंसल्टेंट के पदों में विधि (लॉ) के 11, वित्तीय विश्लेषण (फाइनेंशियल एनालिस्ट) के 22 और सामान्य प्रशासन (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) के 4 पद हैं। वहीं, यंग प्रोफेशनल के पदों में लॉ के 17 और फाइनेंशियल एनालिस्ट के 15 पद शामिल हैं। इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि संबंधित पदों के लिए एसएफआईओ की ओर से विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिन है। ऐसे में जो उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे एसएफआईओ की ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय समय सीमा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस योग्यता वाले कर सकेंगे आवेदन: एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद अनुसार वित्त में ग्रेजुएशन, सीए/आईसीडब्ल्यूए/एमबीए (वित्त), प्रासंगिक क्षेत्र/विषय में पीएचडी/मास्टर डिग्री या एमबीए होनी चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास पोस्ट के अनुसार तय वर्षों का अनुभव और अन्य निर्धारित पात्रता का होना भी अनिवार्य है।

इतनी मिलेगी सैलरी: चयनित अभ्यर्थियों की सैलरी यंग प्रोफेशनल पद के लिए 60,000 रुपए और जूनियर कंसल्टेंट पद के लिए 80,000 रुपए प्रतिमाह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एसएफआईओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें। लास्ट में आवेदन पत्र की एक कॉपी का प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकालकर रख लें।

खुदरा दवा दुकानों की चिंताओं की समीक्षा करेगा सीडीएससीओ

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। इसके साथ खुदरा दवा दुकानों की चिंताओं की समीक्षा करने का भरोसा दिया। इस बैठक के बाद देशभर के कई रिटेल फार्मेसी संघों ने ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) की 20 मई को प्रस्तावित एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल नहीं होने की बात कही। उन्होंने इसे सार्वजनिक हित और जीवनरक्षक दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने की मानवीय जिम्मेदारी का हवाला देते हुए हड़ताल को रद्द करने का फैसला किया। सीडीएससीओ सूत्रों के अनुसार, एआईओसीडी के प्रतिनिधियों ने हाल ही में राष्ट्रीय औषधि नियामक से मुलाकात कर अपनी चिंताएं प्रस्तुत की थीं। इसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि उठाए गए मुद्दों की सक्रिय रूप से समीक्षा की जा रही है और खुदरा दवा क्षेत्र से जुड़े वैध मुद्दों को संबोधित करने के लिए नियामकीय ढांचे पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि केमिस्ट दुकानों के कामकाज में किसी भी तरह की रुकावट से मरीजों, विशेषकर जीवनरक्षक और नियमित दवाओं पर निर्भर कमजोर वर्गों को गंभीर असुविधा हो सकती है, साथ ही आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हो सकती है। इसे देखते हुए कई रिटेल फार्मेसी संघों ने स्थिति की समीक्षा की और नियामक की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त किया है।

नई बुलेट 650 और आंध्र प्रदेश में विशाल कारखाना, रॉयल एनफील्ड ने भविष्य की तैयारी तेज की

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में अपनी अलग पहचान रखने वाली रॉयल एनफील्ड अब एक बड़े बदलाव और विस्तार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ कंपनी अपनी बहुप्रतीक्षित बुलेट 650 को भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती मांग को देखते हुए आंध्र प्रदेश में नया विनिर्माण कारखाना स्थापित करने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया गया है। इन दोनों घोषणाओं ने मोटरसाइकिल प्रेमियों और उद्योग जगत में उत्साह बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में रॉयल एनफील्ड केवल भारतीय बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी स्थिति और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। जल्द दस्तक दे सकती है नई बुलेट 650

रॉयल एनफील्ड की बुलेट दशकों से भारतीय सड़कों की शान मानी जाती रही है। वर्ष 1932 से लगातार उत्पादन में बनी हुई यह मोटरसाइकिल आज भी लाखों लोगों के दिलों में खास जगह रखती है। अब कंपनी इसी ऐतिहासिक

मोटरसाइकिल को और ज्यादा ताकतवर रूप में पेश करने जा रही है। खबरों के मुताबिक बुलेट 650 को अगले एक से दो महीनों के भीतर भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। कंपनी ने इस मोटरसाइकिल की पहली झलक पिछले वर्ष आयोजित मोटरवर्स कार्यक्रम में दिखाई थी। इससे पहले इसका वैश्विक प्रदर्शन इटली के प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल आयोजन में किया गया था। तभी से इस मोटरसाइकिल को लेकर लोगों के बीच उत्सुकता लगातार बनी हुई है। नई बुलेट 650 में कंपनी ने पारंपरिक बुलेट की पहचान को बरकरार रखने की कोशिश की है। मोटरसाइकिल में वही सीधा और मजबूत ढांचा देखने को मिलेगा जिसके लिए बुलेट जानी जाती है। इसके साथ बूंद आकार का ईंधन टैंक, पारंपरिक गोल हेडलाइट और पुराने दौर की झलक देने वाली डिजाइन इसे खास बनाती है। कंपनी ने इसके धातु से बने मजबूत ढांचे और हाथ से बनाई जाने वाली धारियों जैसी पारंपरिक विशेषताओं को भी बरकरार रखा है। हालांकि मोटरसाइकिल में आधुनिक तकनीक और बड़ा इंजन जोड़ा गया है, लेकिन इसका मूल स्वरूप अब भी क्लासिक बुलेट जैसा ही दिखाई देगा। नई बुलेट 650 में 647.95 सीसी क्षमता वाला दो सिलेंडर इंजन दिया जाएगा। यही इंजन कंपनी की अन्य 650 श्रेणी की मोटरसाइकिलों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यह इंजन लगभग 47 ब्रेक हॉर्स पावर की ताकत और 52.3 न्यूटन मीटर टॉर्क उत्पन्न करने में सक्षम बताया जा रहा है। इसके साथ छह गति वाला गियरबॉक्स मिलेगा। पहले की पारंपरिक एक सिलेंडर व्यवस्था की तुलना में यह नया इंजन ज्यादा संतुलित और स्मूद सवारी का अनुभव देगा। खासतौर पर लंबी दूरी की यात्रा और राजमार्ग पर सफर करने वालों को इससे अधिक आराम मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने इसमें आरामदायक चौड़ी सीट और ऊंचे हैंडलबार दिए हैं, जिससे लंबे सफर में थकान कम महसूस होगी। मोटरसाइकिल में आगे की तरफ 19 इंच और पीछे 18 इंच का पहिया दिया जाएगा। वहीं सुरक्षा के लिए दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक और दोहरे चैनल वाली एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली भी मिलने की संभावना है। रेट्रो डिजाइन के बावजूद नई बुलेट 650 आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी।

पश्चिम एशिया संकट के चलते सरकार के उर्वरक सब्सिडी बिल में हुई भारी वृद्धि

एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात लागत बढ़ने से चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में सरकार का उर्वरक सब्सिडी खर्च करीब 15,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस. शर्मा ने सब्सिडी खर्च बढ़ने की पुष्टि की, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, 'सब्सिडी बिल जरूर बढ़ेगा, लेकिन यह कितने प्रतिशत बढ़ेगा, फिलहाल मैं नहीं कह सकती।' लागत बढ़ने के बावजूद शर्मा ने कहा कि 2026 खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की उपलब्धता 'संतोषजनक' बनी हुई है। कुल 390 लाख टन की आवश्यकता के मुकाबले 51 प्रतिशत से अधिक स्टॉक उपलब्ध है और बाकी जरूरत को विभिन्न देशों से आयात के जरिए पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में उर्वरकों का कुल भंडार 200.9 लाख टन है। शर्मा ने कहा, 'कुल मिलाकर स्थिति मजबूत, स्थिर और आरामदायक बनी हुई है।' देश में घरेलू उत्पादन करीब 80,000 टन प्रतिदिन की दर से चल रहा है। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से अब तक 86.2 लाख टन उर्वरक उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 93 लाख टन था। उन्होंने कहा कि यूरिया संयंत्रों के लिए पर्याप्त गैस आपूर्ति उपलब्ध है। भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर के क्षेत्रों से उर्वरकों का आयात बढ़ाया है और अब तक करीब 22 लाख टन उर्वरक आयात किए जा चुके हैं। उर्वरक विभाग यूरिया और जटिल उर्वरकों के उत्पादन के लिए जरूरी अन्य कच्चे माल की उपलब्धता की भी समीक्षा कर रहा है। इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हर साप्ताह सब्सिडी भुगतान किया जा रहा है।

सरकारी नौकरी का मौकाः प्राथमिक शिक्षक समेत 26 पदों पर वैकेंसी

एजेंसी

नई दिल्ली। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के शिक्षा निदेशालय द्वारा समग्र शिक्षा (केंद्र प्रायोजित योजना - सीएसएस) के अंतर्गत विभिन्न कर्मचारियों और शिक्षकों की कुल 26 पदों पर अल्पकालिक संविदा (एसटीसी) आधार पर नियुक्ति हेतु एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह नियुक्ति सरकारी विद्यालयों और समग्र शिक्षा कार्यालयों के लिए किया जाएगा। केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन की ओर से जारी पदों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए संसाधन व्यक्ति के 1, करियर परामर्श के लिए शैक्षणिक संसाधन व्यक्ति के 1, प्राथमिक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) के 10, उच्च प्राथमिक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) के 6, अंशकालिक प्रशिक्षक के 7 और विशेष शिक्षक (माध्यमिक) के 1 पद शामिल हैं। इन पोस्ट पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू, कक्षा प्रदर्शन, प्रायोगिक परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पद अनुसार 12,100 से 27,000 रुपए के बीच प्रति माह होगी।इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद अनुसार बीएड (विशेष शिक्षा) में ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के साथ में करियर काउंसलिंग में डिप्लोमा/काउंसलिंग में मास्टर डिप्लोमा का प्रमाण पत्र, कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं उत्तीर्ण) और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, बीए/बीएससी/बीकॉम में ग्रेजुएशन और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास प्रासंगिक क्षेत्र में तय वर्षों का अनुभव और अन्य निर्धारित पात्रता का होना भी अनिवार्य है। आवेदकों की अधिकतम आयु पद अनुसार 30 से 35 वर्ष के बीच तय की गई है। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वॉक-इन इंटरव्यू 28 मई को सुबह 8.30 बजे से 'सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, दीव' पते पर आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में जो उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल होने वाले हैं, उन्हें केंद्र पर समय से पहुंचने के अलावा अपने साथ भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स की मूल कॉपी के साथ उनके प्रिंट आउट भी ले जाने की सलाह दी जाती है।

बाजार में तहलका मचाने आ रही है स्कॉर्पियो एन

एजेंसी

नई दिल्ली। महिंद्रा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली Mahindra Scorpio N के Facelift वर्जन को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। इसमें किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। किस तरह के फीचर्स के साथ इसे ऑफर किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। महिंद्रा की ओर से भारत में मिड साइज एसयूवी के तौर पर स्कॉर्पियो एन को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा अपनी एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जिसमें कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में कई बदलाव किए जा सकते हैं। इसके डिजाइन में हल्के बदलाव हो सकते हैं। इसके साथ ही इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर भी किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक निर्माता की ओर से टेस्ट की जा रही यूनिट से कुछ फीचर्स की जानकारी मिली है। जिसके मुताबिक एसयूवी को 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेंटर कंसोल डिजाइन में बदलाव, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ही पैनेरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, Level-2 ADAS, हाई बीम असिस्ट, स्पीड लिमिट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स को भी जोड़ा जा सकता है। महिंद्रा की ओर से एसयूवी के इंजन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा दो लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन के विकल्प को ही दिया जा सकता है। जिसके साथ इसे छह स्पीड का मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी दिया जाएगा। एसयूवी को ऑफ रोडिंग क्षमता के साथ भी ऑफर किया जाएगा। निर्माता की ओर से एसयूवी के फेसलिफ्ट की जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के फेसलिफ्ट वर्जन को भारत में 2026 के मध्य तक पेश किया जा सकता है। निर्माता की ओर से लॉन्च के समय ही एसयूवी के फेसलिफ्ट की कीमत की जानकारी दी जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि मौजूदा वेरिएंट्स के मुताबिक फेसलिफ्ट एसयूवी की कीमत में 20 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

पहली बार 96 प्रति डॉलर के पार बंद हुआ रुपया

मुंबई। रुपये में गिरावट का क्रम भी जारी रहा और पहली बार बाजार बंद होते समय एक डॉलर 96 रुपये के ऊपर बोला गया। अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया आज 39 पैसे टूटकर

96.20 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ जो इसका अब तक का निचला बंद भाव है। इससे पहले, बीच कारोबार में यह 96.3950 रुपये प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर तक उतर गया था। भारतीय मुद्रा पिछले कारोबारी दिवस पर 17 पैसे की गिरावट में 95.81 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी। रुपया आज 38 पैसे नीचे 96.19 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। सुबह के कारोबार में यह ऊपर 96.12 रुपये प्रति डॉलर तक गया, लेकिन फिर दबाव में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी से भारतीय मुद्रा दबाव में रही। हालांकि दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक में 0.3 प्रतिशत की गिरावट से रुपये को समर्थन मिला।

भारत-नार्वे व्यापार को करेंगे दोगुना, बढ़ाएंगे हरित साझेदारी और समुद्री सहयोग

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के बीच ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने भारत-नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। यह स्वच्छ ऊर्जा, समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों नेताओं ने 2030 तक भारत और नॉर्वे के बीच मौजूदा व्यापार के मूल्य को दोगुना करने के लक्ष्य पर जोर दिया। वहीं, नार्वे 'हिंद-प्रशांत महासागर पहल' में शामिल होने पर सहमत हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और नॉर्वे के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक एक विशेष भाव के रूप में आज सुबह ओस्लो हवाई अड्डे पर उनके आगमन पर प्रधानमंत्री स्टोर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत-नॉर्वे संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की, जिसमें व्यापार और निवेश, भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर अनुवर्ती कार्रवाई, जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा बदलाव, ब्लू इकोनॉमी और महासागर व्यवस्था, अनुसंधान और उच्च शिक्षा, आर्कटिक और ध्रुवीय सहयोग, अंतरिक्ष, और प्रतिभा की गतिशीलता शामिल हैं। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने भारत में नॉर्वे के उद्यमों द्वारा अधिक निवेश का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने 2030 तक भारत और नॉर्वे के बीच मौजूदा व्यापार के मूल्य को दोगुना करने के लक्ष्य पर जोर दिया, और व्यापार प्रतिनिधियों को विभिन्न क्षेत्रों में गतिशील गठजोड़ की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि टीईपीए के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके और भारत में दस लाख नौकरियों का सृजन किया जा सके।दोनों नेताओं ने अपनी-अपनी टीमों को ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने का निर्देश दिया, जिसमें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, जहाज निर्माण, हरित नौवहन, सुरंग निर्माण और बुनियादी ढांचा, अंतरिक्ष, एआई, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन और जलीय कृषि शामिल हैं। उन्होंने यूएनसीएलओएस के सिद्धांतों की पुनः पुष्टि की और 'हिंद-प्रशांत महासागर पहल' में नॉर्वे के शामिल होने का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे को जून 2026 में फ्रांस में आयोजित होने वाले 'भारत इनोवेट्स 2026' में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच एक 'स्टार्ट-अप इनोवेशन हब' और 'हरित नवाचार हैकाथॉन' स्थापित करने का सुझाव भी दिया। पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर जोर देते हुए, दोनों नेताओं ने 'कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज', 'ऑफशोर विंड' (समुद्री पवन ऊर्जा) जैसी विशिष्ट तकनीकों में अधिक सहयोग का आह्वान किया, और भारत में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में नॉर्वे द्वारा बड़े निवेश की अपील की। दोनों नेता आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवीय अनुसंधान और लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करने पर सहमत हुए और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार कार्यप्रणालियों की पुनः पुष्टि की। उन्होंने अनुसंधान और नवाचार में संयुक्त कार्य पर जोर दिया, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, महासागर, जलवायु, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण खनिज, उभरती प्रौद्योगिकियां और आईटी शामिल हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, वे संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों, योग्यताओं की आपसी मान्यता और छात्रों व शिक्षकों की आवाजाही की संभावनाओं को तलाशने पर सहमत हुए।उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर भी चर्चा की और आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने एक सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए नॉर्वे के समर्थन को दोहराया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की स्पष्ट शब्दों में निंदा की और इस खतरे से निपटने के लिए समन्वित वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया।

नेपाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुधार नहीं होने पर ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी

एजेंसी

काठमांडू। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी करने वाली संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के एशिया पैसेफिक समूह (एपीजी) ने नेपाल को पर्याप्त प्रगति नहीं दिखाने पर 'ब्लैक लिस्ट' में डालने की गंभीर चेतावनी दी है। एपीजी ने कहा है कि 'ग्रे लिस्ट' से बाहर निकलने के लिए आवश्यक सुधारों में नेपाल की प्रगति निराशाजनक रही है। एपीजी ने स्पष्ट किया है कि यह आगामी सितंबर 2026 में होने वाली निर्णायक समीक्षा से पहले अंतिम उच्चस्तरीय हस्तक्षेप है। यानी नेपाल के पास अब चार महीने से भी कम समय बचा है। एपीजी की तीन दिनों तक चलने वाली 'सपोर्ट बैठक' काठमांडू में जारी है। रविवार को काठमांडू पहुंचे एपीजी के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सरकारी निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस बार एपीजी ने अपने उप कार्यकारी सचिव डेविड सैनन के नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल भेजा है। सन् 2002 से एपीजी सचिवालय में कार्यरत सैनन वर्तमान में अपने 24वें पारस्परिक मूल्यांकन का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हें दुनिया के सबसे अनुभवी एफएटीएफ मूल्यांकनकर्ताओं में गिना जाता है। किसी वरिष्ठ अधिकारी की प्रत्यक्ष उपस्थिति को नेपाल की स्थिति की गंभीरता का संकेत माना जा रहा है।

नेपाल में प्रवेश कर रहे भारतीय नागरिक से 570 ग्राम सोना और 20 हजार अमेरिकी डॉलर मिले, गिरफ्तार

काठमांडू। नेपाल के पूर्वी झापा के मेचीनगर स्थित कांकडभिट्टा सीमा क्षेत्र में सशस्त्र प्रहरी बल और कस्टम कार्यालय की संयुक्त टीम ने 570 ग्राम सोना तथा 20 हजार अमेरिकी डॉलर व अन्य विदेशी मुद्रा के साथ एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के अनुसार, भारत से सिटी सफारी वाहन के जरिए नेपाल आ रहे भारत निवासी 39 वर्षीय परम पाठक को विशेष सूचना के आधार पर मंगलवार सुबह जांच के दौरान पकड़ा गया। उसके पास 570 ग्राम सोना, 20 हजार अमेरिकी डॉलर तथा 85 हजार 410 भारतीय रुपये मिले हैं। साथ ही एक भारतीय आधार कार्ड, दो मोबाइल फोन, एक हार्ड डिस्क, एक बैंक चेक तथा सात सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। सशस्त्र प्रहरी के प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक बिष्णु प्रसाद भट्ट ने जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए पाठक को बरामद सामग्री के साथ मेची भंसार कार्यालय कांकडभिट्टा को सौंप दिया गया है। वह किस उद्देश्य से नेपाल में प्रवेश कर रहा था, इसकी फिलहाल जांच जारी है।

नेपाल ने श्रम समझौता करने के लिए 16 देशों को भेजा प्रस्ताव, एक ने भी नहीं दिया जवाब

काठमांडू। नेपाल सरकार ने विदेशी रोजगार को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से 16 देशों के साथ श्रम समझौता प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। युवा, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने उन देशों को प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन अब तक किसी देश ने भी इसका जवाब नहीं दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे ने कहा कि 16 देशों को विदेश मंत्रालय के माध्यम से श्रम समझौते का प्रस्ताव भेजा गया है। ।हालांकि, अब तक किसी भी देश ने नेपाल के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया है। सरकार ने एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देशों के साथ श्रम समझौता करने के उद्देश्य से प्रस्ताव भेजा है। घिमिरे के मुताबिक मंत्रालय ने वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, तुर्की, माल्टा, मालदीव, सर्बिया, साइप्रस, लक्ज़मबर्ग, ब्रुनेई, पोलैंड, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया और बेल्जियम को श्रम समझौते का प्रस्ताव भेजे हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है। इनमें से किसी भी देश ने अब तक नेपाल के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया है।

अमेरिका-ईरान को मनाने में जुटे कतर, सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान, ट्रंप ने हमले को टाला

वाशिंगटन/तेहरान/इस्लामाबाद। दुनिया के प्रमुख और सबसे अहम तेलमार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य पर खिंची तनाव की तलवारों के बीच कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और पाकिस्तान 'अमेरिका और ईरान' के बीच शांति समझौता कराने के प्रयासों पर लगे हुए हैं। मध्यस्थ की भूमिका में विफलता के बावजूद पाकिस्तान ने हार नहीं मानी है। वह अब भी अपने स्तर पर ईरान को मनाने की कोशिश कर रहा है। कतर, सऊदी अरब और यूएई तीनों मिलकर इस संकट का समाधान निकालने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। तीनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वह फिलहाल ईरान पर हमले की अपनी योजना को स्थगित कर दें। अरबी चैनल अल जजीरा, अमेरिकी चैनल सीबीएस न्यूज और पाकिस्तान के चैनल दुनिया न्यूज की रिपोर्ट में ईरान-अमेरिका के मध्य छिड़े विवाद की सुर्खियों को विस्तार से तरजीह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर ईरान पर होने वाले नियोजित हमले को टाल दिया है।

कैलिफोर्निया की मस्जिद पर हमला: सुरक्षा गार्ड समेत 3 की मौत, इस साल अब तक चार बार गोलीबारी से सहमा अमेरिका

एजेंसी

वाशिंगटन । कैलिफोर्निया के सैन डिएगो मस्जिद में हुए हमले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जताया है। उन्होंने इसे भयावह करार दिया। सोमवार सुबह हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक सिक्योरिटी गार्ड और दो संदिग्ध शामिल हैं। अमेरिका में बीते पांच महीनों में गोलीबारी की ये चौथी बड़ी वारदात है। पुलिस के मुताबिक, दोनों संदिग्ध किशोर थे। एक की उम्र 17 साल और दूसरे की 19 साल थी। दोनों के शव मस्जिद के पास एक वाहन में मिले। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि उन्होंने खुद को गोली मारी। इस मामले की जांच हेट क्राइम के एंगल से की जा रही है। हालांकि, हमले के पीछे की वजह पर फिलहाल ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है। गोलीबारी के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'यह एक बेहद गंभीर और दुखद स्थिति है। मुझे शुरुआती जानकारी दी गई है, लेकिन हम इस मामले को बहुत

गंभीरता से देखेंगे।' वहीं, एफबीआई निदेशक काश पटेल के अनुसार एफबीआई गंभीरता से जांच कर रही है। यह हमला इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो में हुआ। यह सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है। परिसर में एक स्कूल भी है, जहां बच्चों को अरबी भाषा, इस्लामिक स्टडीज और कुरान की शिक्षा दी जाती है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि कैलिफोर्निया आपके साथ खड़ा है। जहां परिवार और बच्चे जुटते हैं, जहां लोग शांति से इबादत करते हैं, वहां ऐसा हमला बेहद भयावह है। कैलिफोर्निया में नफरत की कोई जगह नहीं है।'

उन्होंने बताया कि कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल और गवर्नर ऑफिस ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें मौके पर स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर रही हैं। इस साल की ये चौथी बड़ी वारदात है जो अमेरिका में गन कल्चर के बढ़ते चलन की ओर इशारा करता है । ठीक एक महीने पहले यानी 19 अप्रैल 2026 को अमेरिका के लुइसियाना राज्य के श्रेवेपोर्ट शहर में दिल दहलाने वाली वारदात में एक शख्स ने 8 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। इनमें से 7 उसके अपने बच्चे थे। तो 16 फरवरी 2026 को अमेरिका के रोड आइलैंड में हाई स्कूल हॉकी मैच के दौरान गोलीबारी हुई थी। पुलिस के मुताबिक इस हमले में तीन लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें हमलावर भी शामिल था।

23 साल के तुषार कुमार बने यूके के सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर

एजेंसी

लंदन । यूके में भारतीय मूल के और हरियाणा से संबंध रखने वाले 23 वर्षीय काउंसलर तुषार कुमार ने इतिहास रच दिया है। तुषार यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल के सबसे युवा मेयर बन गए हैं। उन्हें एल्स्ट्री और बोरेहमवुड का मेयर नियुक्त किया गया है। तुषार कुमार को 13 मई को बोरेहमवुड के फेयरवे हॉल में आयोजित काउंसिल की मेयर-मेकिंग सेरेमनी में आधिकारिक तौर पर मेयर बनाया गया। इस कार्यक्रम में कई काउंसलर, सामाजिक नेता, कम्युनिटी संगठनों के प्रतिनिधि, स्थानीय लोग, परिवार के सदस्य और दोस्त शामिल हुए। समारोह के बाद तुषार कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'एल्स्ट्री और बोरेहमवुड का मेयर बनना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। 23 साल की उम्र में यूके के इतिहास में भारतीय मूल का सबसे युवा मेयर बनना अविश्वसनीय लगता है। किंग्स कॉलेज लंदन में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई से लेकर अब अपने पसंदीदा शहर की सेवा करने तक का यह सफर किसी सपने जैसा लग रहा है।' अपने भाषण में तुषार कुमार ने बताया कि जब वह 20 साल के थे और किंग्स कॉलेज लंदन में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे थे, तभी पहली बार काउंसलर चुने गए थे।'लंदन डेली' के अनुसार, तुषार ने कहा कि इतनी कम उम्र में मेयर बनना उनके लिए खास मायने रखता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे और ज्यादा युवा लोग स्थानीय लोकतंत्र, समाज सेवा और कम्युनिटी के कामों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित होंगे। तुषार कुमार ने पूर्व मेयर काउंसलर डैन ओजारो का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर रहते हुए उन्हें डैन ओजारो से काफी सहयोग और मार्गदर्शन मिला।

पीएम मोदी का ओस्लो दौरा बढ़ती साझेदारी और साझा महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक : नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टोरे

एजेंसी

ओस्लो। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ते संरक्षणवाद के बीच नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर को बनाए रखने के लिए भारत और नॉर्वे के बीच गहरे सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक मामलों में दबाव के तौर पर कूटनीति, व्यापार और तकनीक के इस्तेमाल का विरोध करने के लिए दोनों देशों को एकजुट रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम स्टोरे ने कहा, 'हमें उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना होगा जो कूटनीति, व्यापार और तकनीक को हथियार बनाते हैं। बढ़ते संरक्षणवाद और ज्यादा तनाव वाले भू-राजनीतिक डायनामिक्स के समय में, नियम-आधारित ऑर्डर के लिए एक साथ खड़े होना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। और हम आज हमारे सामने मौजूद कुछ बड़े मुद्दों पर चर्चा कर पाए हैं, जैसे यूक्रेन में युद्ध और मिडिल ईस्ट में युद्ध। मैं इन मुद्दों को संभालने और सुलझाने के लिए नॉर्वे और भारत के डिप्लोमैट्स के बीच इस सीधे संपर्क की सराहना करता हूं।' उन्होंने आगे कहा कि भले ही भारत और नॉर्वे हमेशा हर मुद्दे पर सहमत न हों, लेकिन दोनों ही पक्के लोकतांत्रिक साझेदार बने हुए हैं, जो सम्मानजनक बातचीत के जरिए मतभेदों को मैनेज करते हैं। स्टोरे ने जोर देकर कहा, 'भारत हमेशा सभी मुद्दों पर एकमत नहीं होता। कोई भी नहीं होता, और हम दोनों सम्मानजनक लोकतंत्र हैं जो उन मुद्दों को लोकतांत्रिक स्टैंडर्ड के हिसाब से संभालते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आज जो चीज हमें एकजुट करती है, वह ज्यादा जरूरी है: यह विश्वास कि सहयोग, एकपक्षीयवाद और आइसोलेशन से बेहतर नतीजे देता है, खासकर जब ग्लोबल चुनौतियों की बात आती है। 'प्रधानमंत्री मोदी के नॉर्वे दौरे की अहमियत बताते हुए, स्टोरे ने कहा कि अनिश्चितता, तेजी से बदलाव और बढ़ते मतभेदों वाली दुनिया में, उन देशों के साथ जुड़ाव को गहरा करना बहुत जरूरी है जो एक जैसे मूल्य रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांत नजरिए में अंतर से ज्यादा जरूरी हैं। नॉर्वे के पीएम ने कहा, 'दुनिया में अनिश्चितताओं और तेजी से बदलाव, ध्रुवीकरण और झगड़ों के समय में, उन देशों के साथ संपर्क मजबूत करना और बनाना जरूरी है, जिनके साथ हम एक जैसे आंतरिक मूल्य रखते हैं। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे दुनिया के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियों के मुकाबले छोटे हैं, और हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। साझेदारी मायने रखती है, खासकर उन लोकतंत्र के बीच जिनके हित एक जैसे हैं और जो वैश्विक समुदाय में एक जैसे नियमों का पालन करते हैं।

युद्ध खत्म करने का रास्ता खोजना मेरा कर्तव्य: लेबनान के राष्ट्रपति औन

एजेंसी

बेरूत। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने स्थानीय कृषि यूनियन नेताओं से बातचीत के दौरान कहा कि इजरायल के साथ जारी प्रत्यक्ष वार्ता का उद्देश्य देश में जारी इजरायली सैन्य अभियानों को समाप्त करने का रास्ता तलाशना है। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, औन ने कहा, 'लेबनान ने वार्ता के लिए जो रूपरेखा तय की है, उसमें इजरायली सेना की वापसी, युद्धविराम, सीमाओं पर लेबनानी सेना की तैनाती, विस्थापित लोगों की वापसी और लेबनान के लिए आर्थिक एवं वित्तीय सहायता शामिल है। इसके अलावा किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा की खबरें गलत हैं।' उन्होंने कहा, ' मैं जिस पद पर हूं और जो मेरी जिम्मेदारी है उसके तहत मेरा कर्तव्य है कि मैं लेबनान और उसके लोगों के खिलाफ युद्ध को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करूं, चाहे इसके लिए कितना भी कठिन कदम क्यों न उठाना पड़े।'

औन ने आगे कहा, 'हम पहले भी युद्धों का अनुभव कर चुके हैं और देखा है कि उन्होंने लेबनान को

किस स्थिति में पहुंचाया। क्या कोई है जो बाद में उसकी कीमत चुका सके?' ही लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लेबनान में इजरायली हमलों में सात लोग मारे गए। इजरायली हमलों में 16 मई तक 2,900 लोगों के मारे जाने की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने की थी।

पिछले सप्ताह अमेरिका और लेबनान के राजदूतों के बीच वाशिंगटन में प्रत्यक्ष वार्ता का तीसरा दौर संपन्न हुआ था, जिसके बाद लेबनान में लागू नाजुक युद्धविराम को अगले 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया।

इस दौरान भी हमले नहीं रुके हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्लाह के 30 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें एक हथियार भंडार, निगरानी चौकियां और वे इमारतें शामिल हैं जिनका इस्तेमाल इजरायली बलों पर हमलों की तैयारी के लिए किया जा रहा था। सेना के अनुसार, इन हमलों में हिज्बुल्लाह के कई लड़ाके भी मारे गए।

अक्टूबर में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा अमेरिका, अटलांटा में होगा आयोजन

एजेंसी

वाशिंगटन । संयुक्त राज्य अमेरिका 30-31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। यह घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने की। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वाशिंगटन इस साल होने वाले कई बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की तैयारी तेज कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे। इसका उद्देश्य जी20 के मुख्य मिशन को आगे बढ़ाना है, यानी वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना। बयान के अनुसार, बातचीत में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और 'खुले बाजारों' तथा 'मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन' को समर्थन देने जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय आई है जब अमेरिका दिसंबर में होने वाले जी20 नेताओं के शिखर

सम्मेलन की मेजबानी की भी तैयारी कर रहा है, जिसकी मेजबानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे।विदेश विभाग ने कहा कि अटलांटा को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह 'कूटनीति, व्यापार और वैश्विक जुड़ाव का एक प्रमुख केंद्र' है, और इसलिए यह इस तरह की अहम चर्चाओं के लिए एक उपयुक्त जगह है।मीडिया नोट में यह भी बताया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप 14-15 दिसंबर को फ्लोरिडा के मियामी स्थित ट्रंप नेशनल डोरल में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे।

यह शिखर सम्मेलन अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के समारोहों के साथ भी जुड़ा होगा। विदेश विभाग ने अभी तक बैठक के एजेंडे, शामिल होने वाले देशों के प्रतिनिधिमंडलों या अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकों की पूरी जानकारी जारी नहीं की है।

भारत, जो जी20 का एक अहम सदस्य है और अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भी है, इन चर्चाओं पर करीबी नजर रखेगा। खासकर वैश्विक व्यापार, सप्लाई चेन की मजबूती और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर। भारत लगातार बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार, ग्लोबल साउथ की ज्यादा भागीदारी और सेमीकंडक्टर तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सुरक्षित सप्लाई चेन की मांग करता रहा है।जी20 में अमेरिका, भारत, चीन, रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ जैसे बड़े अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर लागू की नई व्यवस्था

एजेंसी

तेहरान । ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नई व्यवस्था लागू करने का ऐलान कर दिया है। नई अथॉरिटी बनाई है जो समुद्री संचालन पर रियल टाइम निगरानी रखेगी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल स्ट्रेट के प्रबंधन हेतु नया निकाय 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (पीजीएसए)' बनाने की घोषणा की गई है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि यह संस्था होर्मुज स्ट्रेट के संचालन और ताजा घटनाक्रमों पर 'रियल-टाइम अपडेट' जारी करेगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब पश्चिम एशिया में तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि अमेरिकी विमान बड़ी मात्रा में हथियार लेकर इजरायल पहुंच गए हैं और इजरायली सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। पीजीएसए समुद्री गतिविधियों की निगरानी और संचालन से जुड़ी सूचनाएं साझा करेगी। ईरान पहले ही जहाजों के लिए नए ट्रांजिट नियम और अनुमति प्रणाली लागू करने के संकेत दे चुका था। दो दिन पहले ही तेहरान ने एक नए सिस्टम की बात की थी। ईरान के अनुसार, उनका ये सिस्टम फ्रीडम प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी योजना साझा की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा, ' ईरान ने अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरक्षा की गारंटी के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में यातायात प्रबंधन के लिए एक पेशेवर तंत्र तैयार किया है, जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। इस प्रक्रिया में केवल वाणिज्यिक जहाज और ईरान के साथ सहयोग करने वाले पक्ष ही लाभान्वित होंगे।

ट्रंप प्रशासन का क्यूबा के खिलाफ बड़ा एक्शन, 11 अधिकारियों और 3 सरकारी संगठनों पर लगाए नए प्रतिबंध

एजेंसी

वाशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा के 11 अधिकारियों और तीन सरकारी संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। विदेश मंत्री मार्को रुबियो का कहना है कि क्यूबा की सरकार लोगों पर दमन कर रही है, सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है और विदेशी खुफिया तथा सैन्य गतिविधियों को समर्थन दे रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सख्त कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों का मकसद क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार और सेना को अवैध आर्थिक संसाधनों से दूर रखना है। इन प्रतिबंधों की घोषणा 1 मई, 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश 14404 के तहत की गई थी। इसका लक्ष्य वे लोग हैं जो 'क्यूबा में दमन के लिए और संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा व विदेश नीति के लिए खतरों के

लिए जिम्मेदार हैं।' मार्को रुबियो ने कहा कि जिन 11 लोगों पर कार्रवाई हुई है, उनमें क्यूबा सरकार और सेना से जुड़े कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि इनमें से कई लोग क्यूबा के नागरिकों पर दमन करने में शामिल रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि यह कदम क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार से पैदा हो रहे सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए चलाए जा रहे बड़े अभियान का हिस्सा है। साथ ही उन लोगों और संस्थाओं को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जो क्यूबा सरकार को आर्थिक या अन्य तरह का समर्थन दे रहे हैं। इन प्रतिबंधों में क्यूबा के कई वरिष्ठ अधिकारियों और सैन्य हस्तियों को भी निशाना बनाया गया है, जिनमें एडी मैनुअल सिएरा एरियस, ऑस्कर अलेजांद्रो कैलेजस वालकार्स, रोसाबेल गामोन वर्डे, जोकिन क्विंटास सोला, जुआन एस्टेबान लाजो हर्नांडेज़, विसेंट डे ला ओ लेवी और मायरा अरेविच मारिन शामिल हैं। अन्य जिन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, वे हैं जोस मिगुएल गोमेज़ डेल वैलिन, राउल विलर केसेल, रॉबर्टो टॉमस मोरालेस ओजेडा और यूजेनियो आर्मंडो राबिलेरो अगुइलेरा। रुबियो ने कहा कि ये लोग क्यूबा की खराब आर्थिक स्थिति, वहां के लोगों की परेशानियों और विदेशी खुफिया व सैन्य गतिविधियों में क्यूबा के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों और हफ्तों में और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, जिन लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनकी अमेरिकी अधिकारी क्षेत्र में मौजूद संपत्तियां और आर्थिक हित फ्रीज कर दिए जाएंगे। साथ ही अमेरिकी नागरिक और कंपनियां इनके साथ किसी भी तरह का आर्थिक लेन-देन नहीं कर सकेंगी, जब तक कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की विशेष अनुमति न हो।

विदेशी कलाकारों ने सुनाई आरती 'ओम जय जगदीश', पीएम मोदी बोले 'ये एकता का प्रतीक'

एजेंसी

ओस्लो । भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे में देसी-विदेशी कलाकारों ने भाव विभोर कर दिया। पीएम अनुपम प्रस्तुति से खासा प्रभावित हुए और उन्होंने इसकी सराहना की।

प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट के जरिए भावनाएं व्यक्त की। एक के बाद एक तीन पोस्ट्स में मनोहर प्रस्तुतियां दिखीं। उन्होंने लिखा, 'ओस्लो में आज भारतीय समुदाय द्वारा किए गए स्वागत कार्यक्रम में 'रिदम्स ऑफ इंडिया' की प्रस्तुति ने भारत की सांस्कृतिक विविधता की खूबसूरत झलक पेश की। सत्त्रिया से भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी से ओडिसी, कथक से मोहिनीयट्टम तक – हर नृत्य शैली अपने साथ वर्षों की साधना, अनुशासन और उत्कृष्टता की परंपरा लेकर चलती है।' पीएम मोदी ने आगे लिखा, 'मुझे गर्व है कि हमारा प्रवासी भारतीय समुदाय भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत और सशक्त बनाए हुए है।'

भारत के प्रधानमंत्री के सामने छोटी बच्चियों ने भी शास्त्रीय नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। पीएम मोदी ने लिखा, 'एक प्रमुख स्वागत समारोह के दौरान नाट्यालय डांस स्कूल के समूह ने भरतनाट्यम से जुड़ी 'अलारिप्पु' प्रस्तुति दी। यह टीम लगभग तीन दशकों से नॉर्वे में भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को लोकप्रिय बनाने का कार्य कर रही है। ऐसे प्रयास वास्तव में सराहनीय हैं।'

प्रधानमंत्री के स्वागत में जुगलबंदी की भी मनोहर प्रस्तुति हुई। देसी विदेशी कलाकारों की मंडली आरती ओम जय जगदीश गाती दिखी। पीएम ने लिखा, ''साथ साथ' की प्रस्तुति संगीत, संस्कृति और साझा कलात्मक भावना के माध्यम से एकता का सुंदर प्रतीक रही। भारतीय और पाश्चात्य शास्त्रीय परंपराओं के इस मधुर संगम के लिए बैराट ड्यू म्यूजिक इंस्टीट्यूट की टीम का आभार।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओस्लो पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्टोरे ने भी उनका पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा और वैश्विक मुद्दों समेत कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। भारत और नॉर्वे के संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी बातचीत की गई।

ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, कहा- जल्द निर्णय ले, अन्यथा हो सकते हैं गंभीर परिणाम

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तेहरान को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान को वार्ता प्रक्रिया पर जल्द स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि बातचीत में लगातार हो रही देरी स्थिति को और जटिल बना सकती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान जानबूझकर वार्ताओं को लंबा खींच रहा है। अमेरिकी पक्ष की ओर से यह संकेत दिया गया है कि यदि निकट भविष्य में किसी समझौते की दिशा में ठोस प्रगति नहीं होती, तो हालात अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा कि अमेरिका लंबे समय तक अनिश्चितता की स्थिति में नहीं रहना चाहता। उन्होंने यह भी कहा कि अब निर्णय लेने का समय आ गया है और ईरान को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक उच्चस्तरीय बैठक होने की संभावना है। इस बैठक में ईरान से जुड़े मुद्दों और आगे की अमेरिकी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। रिपोर्टों के अनुसार, संभावित विकल्पों में कूटनीतिक दबाव बढ़ाने के साथ अन्य रणनीतिक कदमों पर भी विचार किया जा सकता है।

जो बाइडन प्रशासन ने अदाणी ग्रुप पर राजनीति से प्रेरित मामला चलाया : अमेरिकी सांसद

एजेंसी

वाशिंगटन । रिपब्लिकन सांसद लांस गुडेन ने जो बाइडन प्रशासन पर अदाणी ग्रुप पर राजनीति से प्रेरित मामला चलाने का आरोप लगाया। साथ ही, अदाणी एंटरप्राइजेज और यूएस ट्रेजरी के बीच 275 मिलियन डॉलर के समझौते का स्वागत किया और इसे भारत-अमेरिका संबंधों के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। समाचार एजेंसी बात करते हुए अमेरिकी सांसद ने कहा कि हम इस परिणाम से बहुत खुश हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि गौतम अदाणी को इस सब से गुजरना पड़ा।

अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) ने ऐलान किया कि अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने ईरान से संबंधित प्रतिबंधों के 32 कथित उल्लंघनों को लेकर संभावित नागरिक दायित्व को निपटाने के लिए 275 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई है। गुडन ने इससे पहले भी बाइडन प्रशासन में न्याय विभाग और अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी दोनों को पत्र लिखकर अदाणी समूह के अभियोजन पर सवाल उठाए थे। गुडन ने कहा कि उन्होंने ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष बार-बार चिंताएं उठाई थीं।

उन्होंने कहा, 'हमने बाइडन न्याय विभाग से संपर्क किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 'उन्होंने आगे कहा, 'यह उन शुरुआती मुद्दों में से एक था जो मैंने ट्रंप प्रशासन के दौरान न्याय विभाग के समक्ष उठाए थे, और मुझे पता है कि वे इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और सही काम करने को प्राथमिकता दे रहे हैं।' टेक्सास के सांसद ने इस मुद्दे को सबसे पहले उनके ध्यान में लाने के लिए भारतीय-अमेरिकी कारोबारी अरुण अग्रवाल को भी श्रेय दिया।

गुडन ने बताया कि मुझे इस मामले के बारे में पहली बार जानकारी टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन अरुण अग्रवाल की ओर से दी गई।

उन्होंने कहा कि भारत में एक व्यक्ति है जो हमारे डेमोक्रेट न्याय विभाग द्वारा राजनीतिक अभियोजन का शिकार है। गुडन ने बताया कि उनका मानना है कि इस मामले से अमेरिका में भारतीय निवेश हतोत्साहित होने का खतरा है।

उन्होंने कहा, 'मैंने शुरू से ही यह माना था कि अदाणी को अमेरिका में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी कंपनी और उनके परिवार द्वारा भारत भर में किए जा रहे अच्छे कार्यों को जारी रखना ही सही था।' गुडन ने पहले भी अदाणी पर अभियोग के पीछे राजनीतिक मकसद होने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने आईएएनएस को बताया, 'मेरा मानना है कि न्याय विभाग में जिन लोगों ने इसके लिए दबाव डाला, उनके सोरोस से संबंध थे।' उन्होंने तर्क दिया कि ये आरोप 'राष्ट्रपति ट्रंप के चुने जाने के ठीक बाद लगाए गए थे, मानो किसी देश में निवेश को हतोत्साहित करने के लिए, ताकि राष्ट्रपति ट्रंप अपने चुनावी वादों में से एक, यानी अमेरिका को फिर से महान बनाने के वादे को पूरा न कर सकें।' अमेरिका में अदाणी समूह के भविष्य के निवेशों के बारे में पूछे जाने पर, गुडन ने कहा कि टेक्सास को इससे काफी लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा, 'हां, मुझे विश्वास है कि वे टेक्सास में निवेश करेंगे और उम्मीद है कि अन्य राज्यों में भी करेंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि अमेरिका, हमारा कार्यबल, हमारा ऊर्जा उद्योग और अन्य कई उद्योग जिनमें अदाणी समूह शामिल है, सभी को इससे लाभ होगा।'

page 1 and 8 may 20_page 1 Mar 25 final ds.qxd 5/20/2026 12:49 AM Page 2

स्थानीय समाचार

देश का पहला वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ी रखरखाव केंद्र का जोधपुर में निर्माण कार्य जारी

जोधपुर, 19 मई । राजस्थान के Jodhpur में देश का पहला वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ी रखरखाव केंद्र तेजी से बनाया जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग 360 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यह केंद्र भारतीय रेल को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने 26 फरवरी 2024 को इस परियोजना की नींव रखी थी। परियोजना के पहले चरण का कार्य जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रेलवे मंत्रालय ने दूसरे चरण के लिए 95 करोड़ रुपये की नई निविदा भी जारी कर दी है, जिससे निर्माण कार्य में और तेजी आएगी।

इस रखरखाव केंद्र में 600 मीटर लंबी आधुनिक रेल पटरी बनाई जाएगी, जहाँ एक साथ 24 रेल डिब्बों यानी लगभग तीन पूरी वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ियों का रखरखाव किया जा सकेगा। दूसरे चरण में आधुनिक भवन, कार्यशाला, प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण प्रयोगशाला, पहिया भंडारण व्यवस्था और उच्च तकनीकी जांच सुविधाएँ तैयार की जाएँगी।

इस परियोजना के पूरा होने के बाद जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। निर्माण कार्य, तकनीकी सेवाओं और संचालन से जुड़े हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा स्थानीय व्यापार, होटल और परिवहन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह रखरखाव केंद्र देश में लंबी दूरी की तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल सेवाओं को नई मजबूती देगा तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अवैध खनन में लिप्त 5 वाहन जब्त

कठुआ, 19 मई (हि.स.)। अवैध खनन के खिलाफ जारी अभियान के तहत कठुआ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 वाहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के नेतृत्व में की गई।

पुलिस के अनुसार थाना लखनपुर क्षेत्र के कीढ़ियां-गंडियाल नाके पर गश्त के दौरान 3 ट्रकों को बिना वैध अनुमति निर्माण सामग्री ले जाते हुए पकड़ा गया।

वहीं तो हीरानगर के बाकू गुराह क्षेत्र में पुलिस टीम ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने पर जब्त किया। जब्त किए गए सभी 5 वाहनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए खनन विभाग कठुआ को सौंप दिया गया है।

महिला की मौत पर परिवार वालों ने डॉक्टरों की लापरवाही को बताया जिम्मेदार

जम्मू, 19 मई (हि.स.)। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल बक्शी नगर में 33 वर्षीय महिला की मौत पर परिवार वालों ने डॉक्टरों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। मृतका की पहचान नीश देवी पत्नी रवि कुमार के रूप में हुई है।

मृतका के पति रवि कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी नीशू देवी को हार्ट की दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने कल उसे अस्पताल भर्ती करवाया, लेकिन उसकी बीमारी की ओर कोई गौर नहीं किया गया। आज सुबह उसके नाक में पाइप डाल दी और कोई भी बड़ा डॉक्टर उसकी पत्नी को देखने नहीं आया। इलाज में लापरवाही के चलते आज सुबह नीशू की मौत हो गई।

परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन शव ले जाने के लिए उन्हें एंबुलेंस नहीं दे रहा है। प्रशासन का कहना है कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। मृतका के पति ने कहा कि वह दिहाड़ी लगाता है और गरीब परिवार से है। उनके पास गाड़ी करके ले जाने के पैसे तक नहीं बचे। उधार पैसे लेकर पत्नी का इलाज करवा रहे थे, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई गरीब आदमी अस्पताल में मर जाता है और उसके पास पैसे नहीं है तो क्या उसकी लाश घर नहीं पहुंचेगी।

एमजीएनआरईजीए में खराब प्रदर्शन के चलते बीडीओ के वेतन पर लगाई रोक

किश्तवाड, 19 मई (हि.स.)। सहायक आयुक्त विकास (एसीडी) किश्तवाड ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत लक्ष्यों के खराब कार्यान्वयन और प्राप्ति न होने के कारण जिले के कई ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) के वेतन रोकने का आदेश दिया है। एसीडी किश्तवाड मनोज कुमार (जेकेएएस) द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार जिले को अप्रैल 2026 तक एमजीएनआरईजीए के तहत 15,000 मानवदिवस सृजित करने का लक्ष्य दिया गया था। हालांकि पूरे जिले में केवल 70 मानवदिवस ही सृजित किए गए जो स्वीकृत लक्ष्य के मुकाबले मात्र 0.47 प्रतिशत उपलब्धि है। आदेश में कहा गया है कि बार-बार निर्देश देने, स्वीकृत वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) और संबंधित ब्लॉकों को लक्ष्यों की सूचना देने के बावजूद अधिकारी कार्यों के प्रभावी निष्पादन, रोजगार कार्ड धारकों को जुटाने और योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में विफल रहे। प्रशासन ने पाया कि खराब प्रदर्शन ने ग्रामीण रोजगार कार्ड धारकों के अधिकारों और हकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया और एमजीएनआरईजीए अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया। एसीडी ने बताया कि पहले संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर खराब प्रदर्शन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसमें वेतन रोके जाने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना भी शामिल थी। कुछ अधिकारियों ने जवाब प्रस्तुत किए लेकिन प्रशासन ने उन्हें अस्पष्ट, असंतोषजनक और ठोस औचित्य से रहित बताया जबकि कई अन्य निर्धारित समय के भीतर जवाब देने में विफल रहे।

जनगणना 2027 के तहत सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान ने पकड़ी रफ्तार, विधायकों ने की भागीदारी की अपील

कठुआ, 19 मई (हि.स.)। जनगणना 2027 के तहत चल रहे सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान ने जिले में गति पकड़ ली है। अभियान के तीसरे दिन जसरोटा विधायक राजीव जसरोटिया और कठुआ विधायक डॉ. भारत भूषण ने स्वयं अपना सेल्फ एन्यूमरेशन पूरा कर इस राष्ट्रीय प्रक्रिया के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

कठुआ में विधायक डॉ. भारत भूषण का सेल्फ एन्यूमरेशन उनके निवास पर अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त सुरिंदर मोहन शर्मा की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ, जहां जिला प्रशासन की टीम ने उन्हें डिजिटल प्रक्रिया की चरणबद्ध जानकारी दी। वहीं तहसीलदार कठुआ विक्रम कुमार ने अपनी टीम के साथ विधायक राजीव जसरोटिया को सुचारू रूप से प्रक्रिया पूरी करने में सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर दोनों विधायकों ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि सेल्फ एन्यूमरेशन एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जो देश में सटीक और समावेशी जनसंख्या आंकड़े तैयार करने में सहायक है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए घर बैठे इस प्रक्रिया को पूरा करें।

इधर, जिले भर में चार्ज अधिकारियों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम, जनसंपर्क अभियान और विशेष शिविरों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। पंचायत, वार्ड और गांव स्तर पर लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन के महत्व, प्रक्रिया और लाभों के बारे में जानकारी देकर अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने बताया कि जिले में इस अभियान को लेकर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना सेल्फ एन्यूमरेशन अवश्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने इस कार्य के लिए विशेष टीमें, जागरूकता शिविर और सहायता तंत्र स्थापित किए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और समावेशी विकास की मजबूत नींव रखी जा सके।

33 लाख की लागत से नगरी के ऐतिहासिक आयरन ब्रिज का पुनर्निर्माण शुरू, विधायक डॉ. भारत भूषण ने किया शुभारंभ

कठुआ, 19 मई (हि.स.)। कठुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. भारत भूषण ने मंगलवार को नगरी स्थित ऐतिहासिक आयरन ब्रिज के पुनर्निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। लगभग 33 लाख की लागत से इस पुल की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त कठुआ सुरिंदर मोहन शर्मा, ब्लॉक विकास अधिकारी नगरी-परोल प्रदीप सिंह, तहसीलदार नगरी आना जमवाल, नगर समिति नगरी के कार्यकारी अधिकारी पीआर सांगड़ा सहित लोक निर्माण एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं श्री माता बाला सुंदरी मंदिर के श्रद्धालु भी कार्यक्रम में शामिल हुए। गौरतलब है कि नगरी का यह ऐतिहासिक पुल अगस्त 2025 में आई अचानक बाढ़ के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। यह पुल नगरी के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है जिसके खराब होने से स्थानीय लोगों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।इस मौके पर बोलते हुए विधायक डॉ. भारत भूषण ने कहा कि यह पुल क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा के समान है और इसकी मरम्मत स्थानीय जनता की लंबे समय से लंबित मांग थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार क्षेत्र में मजबूत एवं टिकाऊ आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास में सुदृढ़ बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि कठुआ विधानसभा क्षेत्र में सड़कों, पुलों, जलापूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई विकास कार्य जारी हैं। पुल के पुनर्निर्माण से क्षेत्र के लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी और यात्रियों, विद्यार्थियों तथा किसानों को विशेष लाभ होगा।

पीएम सूर्य घर योजना व स्मार्ट मीटरिंग की प्रगति की समीक्षा

कठुआ, 19 मई (हि.स.)। डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 3228 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 1915 घरों में सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं और 1828 को चालू किया जा चुका है।

डीसी ने अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत और गांव स्तर पर कैंप आयोजित कर योजना के लाभ और प्रक्रिया की जानकारी देने पर जोर दिया। स्मार्ट मीटरिंग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कवरेज बढ़ाने और पारदर्शिता व ऊर्जा दक्षता सुधारने के निर्देश दिए।

हटली मोड़ पर गौ-तस्करी नाकाम, 31 मवेशी बचाए, ट्रक जब्त

कठुआ, 19 मई (हि.स.)। कठुआ पुलिस ने हटली पुलिस पोस्ट अधिकार क्षेत्र में गौ-तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे हटली मोड़ क्षेत्र में 31 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। इस दौरान तस्करी में इस्तेमाल एक ट्रक को भी जब्त कर लिया गया।

जानकारी के अनुसार एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के समग्र निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा हटली मोड़ पर नाका लगाकर वाहनों की जांच की जा रही थी।

इसी दौरान पंजाब से जम्मू-कश्मीर की ओर आ रहे एक संदिग्ध ट्रक नंबर एचआर55डब्लू-6756 को जांच के लिए रुकने का संकेत दिया गया।

पुलिस को देखकर चालक ने ट्रक को नाके से कुछ दूरी पहले ही रोक दिया और मौके से फरार हो गया। जब पुलिस टीम ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 31 मवेशी को अमानवीय तरीके से भरा हुआ पाया गया। पुलिस ने सभी मवेशियों को सुरक्षित छुड़ाकर ट्रक को जब्त कर लिया। इस संबंध में थाना कठुआ में एफआईआर नंबर 246/2026 धारा 223 बीएनएस और 11 पीसीए एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

कठुआ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गौ-तस्करी पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को 112 या 09858034100 पर दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

श्री अमरनाथ यात्रा से पहले डीसी और एसएसपी कठुआ ने हीरानगर के लॉजमेंट केंद्रों का किया निरीक्षण

कठुआ, 19 मई (हि.स.)। आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा लेने हेतु डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने हीरानगर उपमंडल के नामित लॉजमेंट केंद्रों का निरीक्षण किया।

इस दौरान उनके साथ एसएसपी कठुआ मोहित शर्मा, एडीसी कठुआ विशवजीत सिंह और एसडीएम हीरानगर फूलैल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डीसी ने केंद्रों पर स्वच्छता, पेयजल, बिजली, बिस्तर, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार रखें और विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखें ताकि यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। एसएसपी कठुआ ने भी सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करते हुए सभी एजेंसियों के बीच तालमेल पर जोर दिया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि यात्रा से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी।

रेल वैगन के स्क्रैप से तैयार इको हेरिटेज गार्डन बना ग्रीन इनोवेशन की मिसाल

भोपाल, 19 मई। जहाँ आमतौर पर फैक्ट्रियों से निकलने वाले स्क्रैप को बेकार मान लिया जाता है, वहीं झाँसी का वैगन मरम्मत कारखाना उसी स्क्रैप से एक नई मिसाल पेश कर रहा है। अब यह कारखाना केवल वैगनों की मरम्मत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और रचनात्मक सोच का एक जीवंत उदाहरण बन गया है। करीब डेढ़ सदी पुराना यह कारखाना वर्ष 882 में स्थापित हुआ था, जब देश में रेलवे नेटवर्क विस्तार की शुरुआत हो रही थी। इंडियन मिडलैंड रेलवे ने झाँसी को इस महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में चुना और 895 में यहाँ. स्टीम इंजन व यात्री डिब्बों की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। आज 84 एकड़ में फैला यह कारखाना भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा वैगन मरम्मत केंद्र बन चुका है, जहाँ हर महीने करीब 925 मालवाहक वैगनों की मरम्मत की जाती है। आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित कर्मचारियों की मदद से यहाँ डिफेंस वैगनों समेत सभी प्रकार के वैगनों की ओवरहॉलिंग की जाती है, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता काफी उच्च मानी जाती है। हालांकि, अब इस कारखाने की पहचान केवल उसके काम तक सीमित नहीं रही। वर्ष 2023 में शुरू की गई एक नई पहल ने इसे एक अलग मुकाम दिया है। मरम्मत के दौरान निकलने वाले स्क्रैप का उपयोग कर करीब 5 एकड़ क्षेत्र में इको हेरिटेज गार्डन तैयार किया गया, जो आज लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है।

इस गार्डन में स्क्रैप से तैयार किए गए इंडिया गेट और ताजमहल जैसे मॉडल विशेष आकर्षण का केंद्र हैं, जोदेखने वालों को चौंका देते हैं। इसके अलावा ट्री हाउस, झोपड़ियाँ, फिश पार्क, अंब्रेला गार्डन, वॉल आर्ट और 30 पोर्ट्रेट्स इसे एक अनोखा और जीवंत स्वरूप देते हैं। यह पहल स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अनुपयोगी समझी जाने वाली सामग्री को भी रचनात्मकता के माध्यम से उपयोगी और आकर्षक बनाया जा सकता है। कारखाने में स्थापित रेल म्यूज़ियम भी अपनी अलग पहचान रखता है, जहाँ रेल मॉडल और कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय रेल की समृद्ध विरासत को नए और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

झाँसी का यह वैगन मरम्मत कारखाना अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है, जो यह संदेश देता है कि नई सोच और नवाचार से स्क्रैप भी सृजन की मजबूत नींव बन सकता है।

हमारी जनगणना हमारा विकास

गृह मंत्रालय भारत सरकार

(जनगणना 2027 का पहला चरण)
स्व-गणना (Self Enumeration) से जुड़े सामान्य प्रश्न और उत्तर (भाग-2)

स्व-गणना क्या है?
स्व-गणना एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें आप प्रगणक की प्रतीक्षा किए बिना, स्वयं SE पोर्टल (se.census.gov.in) पर अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं

स्व-गणना के क्या लाभ हैं?
- अपनी सुविधा से जानकारी भर सकते हैं
- गोपनीयता सुनिश्चित
- जनगणना प्रक्रिया को तेज़ और कुशल बनाती है

स्व-गणना पोर्टल में लॉग-इन कैसे करें?
- राज्य / संघ राज्य क्षेत्र चुनें
- मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल (वैकल्पिक) भरें
- OTP द्वारा सत्यापन करें
- स्व-गणना शुरू करें

अपने घर का सही स्थान कैसे चिन्हित करें?
- जिला / पिनकोड चुनें
- क्षेत्र / लैंडमार्क दर्ज करें
- मैप पर ज़ूम करें और घर के पास लोकेशन मार्क करें (सटीक पता न दिखने पर घबराएं नहीं)
- सही लोकेशन चिन्हित करना आवश्यक है

क्या मैं अपनी जानकारी बाद में संशोधित कर सकता / सकती हूँ?
- सबमिट करने से पहले एडिट कर सकते हैं
- सबमिशन के बाद, प्रगणक के आने पर ही बदलाव संभव होगा

क्या स्व-गणना (SE) पोर्टल को भारत के बाहर से एक्सेस किया जा सकता है?
नहीं, यह सुविधा केवल भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर उपलब्ध है

यदि सबमिशन के बाद गलती पता चले तो क्या करें?
प्रगणक के आने पर SE ID के साथ सुधार करवाया जा सकता है

क्या मैं फॉर्म सेव करके बाद में पूरा कर सकता / सकती हूँ?
हां, आप प्रोग्रेस सेव कर सकते हैं और निर्धारित समय के भीतर फॉर्म पूरा कर सकते हैं

टोल फ्री - 1855

CBC 19108/13/0101/2627

चलो निभाएं अपनी ज़िम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी CensusIndia2027